Website : www.mantrabharat.com
जुनून है सच लिखने का
E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 45
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शनिवार, 21 फरवरी, 2026

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में ...
4 आखिर जातीय, धार्मिक व क्षेत्रीय भावनाओं ...
7 क्वालकॉम, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में ...

संक्षिप्त न्यूज

जोशीमठ में सरकारी बिल्डिंग में Namaz पर मचा बवाल, पहल संगठनों ने जताया कड़ा विरोध

उत्तराखंड के पहाड़ी कस्बे जोशीमठ में उस समय तनाव बढ़ गया जब मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने कथित तौर पर बिना आधिकारिक अनुमति के एक सरकारी इमारत के अंदर नमाज अदा करना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह इमारत स्थानीय नगरपालिका द्वारा खेल विभाग को आवंटित की गई थी और इसे टेबल टेनिस सुविधा के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव था। हालांकि, पिछले कई दिनों से इस परिसर का कथित तौर पर सामूहिक नमाज के लिए उपयोग किया जा रहा है और नमाजियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस संबंध में कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने धार्मिक प्रार्थनाओं पर आपत्ति जताई

निवासियों ने सरकारी संपत्ति का धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह स्थान विशेष रूप से खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित था। उनका दावा है कि नगरपालिका ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस भवन का उपयोग नमाज़ अदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों ने कहा कि किसी भी सरकारी भूमि या सरकारी भवन में नमाज़ अदा करने की अनुमति देना अवैध है।

हिंदू समूहों ने ज्ञापन सौंपा

स्थानीय लोगों ने कहा है कि वे परिसर को पूजा-पाठ के लिए इस्तेमाल किए जाने का विरोध जारी रखेंगे। क्षेत्र के हिंदू समूहों ने इस संबंध में अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि मामला अब सुलझ गया है और हिंदू संगठनों द्वारा प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन पर कार्रवाई की गई है।

असम को बड़ी सौगात:

14 मार्च को बराक घाटी आएंगे पीएम मोदी, 22,000 करोड़ के गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेसवे की रखेंगे नींव

असम में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बराक घाटी के विकास के लिए बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। शुक्रवार को सिलचर में संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 मार्च को बराक घाटी का दौरा करेंगे और राज्य के बुनियादी ढांचे को बदलने वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और 22,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे।

शर्मा ने सिलचर में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं को बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से गुवाहाटी और सिलचर के बीच का सफर मौजूदा आठ घंटे से घटकर साढ़े चार घंटे का रह जाएगा। शर्मा ने बताया कि इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई है। उन्होंने कहा, भूमि अधिग्रहण का कार्य भी अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है और सड़क निर्माण जल्द ही शुरू होगा।

शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान सिलचर फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। असम में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सिलचर में प्रस्तावित 'ग्रीनफील्ड' हवाई अड्डा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बृहस्पतिवार को इसके लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, अब इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी की जरूरत होगी... समय कम बचा है लेकिन हम मार्च तक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश करेंगे। अगर यह संभव नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव के बाद होगा। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है।

'उगते सूरज की भूमि' को पीएम मोदी की बधाई, Arunachal-Mizoram के Foundation Day पर दिया खास संदेश

20 फरवरी का दिन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज ही के दिन वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 'उगते सूरज की भूमि' और 'पहाड़ी लोगों की भूमि' के रूप में प्रसिद्ध ये दोनों राज्य सामरिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से भारत के अभिन्न अंग हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य की स्थापना दिवस पर बधाई दी और कामना की कि आने वाले समय में ये राज्य विकास की नयी ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मनोरम दृश्यों और असाधारण सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि इसके उत्साही और मेहनती नागरिक राष्ट्र की प्रगति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही राज्य की विविध जनजातीय संस्कृति राष्ट्र को अपार समृद्धि प्रदान करती है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''अरुणाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं... आशा है कि आने वाले समय में राज्य विकास की नयी ऊंचाइयों को छूता रहेगा।''

बिहार के बिगड़ते Law and Order पर RJD का हल्लाबोल, Tejashwi बोले- CM Nitish बेखबर, अपराधी बादशाह

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है और सरकार के संरक्षण के कारण अपराधी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए यादव ने दावा किया कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से आपराधिक तत्व बेखौफ और संरक्षित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अपराध भाजपा शासित राज्यों में सबसे अधिक है और बिहार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है।

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए उन्हें बेखबर बताया और कहा कि वे पूरे राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपराध अपने चरम पर है। अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से हम कहते आ रहे हैं कि अपराधी बादशाह बन गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री बेखबर हैं... अपराध भाजपा शासित राज्यों में सबसे अधिक है।

उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है... अगर कोई घटना घटती है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह मुद्दा उठाए ताकि जनता को न्याय मिल सके, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल उलट है - सत्ताधारी दल विपक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त है। ये लोग न तो उचित जवाब देते हैं और न ही कोई कार्रवाई करते हैं। इससे पहले दिन में, आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी एम्स पटना के पास हाल ही में हुई एक लड़की की मौत को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला किया और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि कुछ जिलों में लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। पूरा देश और बिहार देख रहा है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पीएम मोदी की क्वालकॉम सीईओ से अहम बैठक, सेमीकंडक्टर-6जी पर हुई बात

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो एमोन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस में प्रौद्योगिकी सीईओ से मुलाकात की। यह बैठक क्वालकॉम के सीईओ द्वारा शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण के बाद हुई। क्रिस्टियानो एमोन ने अपने संबोधन में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मोबाइल उपकरणों के बारे में हमारी सोच को मौलिक रूप से बदल देगी और इस बात पर जोर दिया कि इस दिशा में क्वालकॉम द्वारा किया गया कार्य ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण करेगा जो सभी उपकरणों में इस भविष्य को साकार करने में सहायक होगा।

उन्होंने कहा कि हम अपने स्मार्टफोन को एक अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। भविष्य में, औद्योगिक क्षेत्र में रोबोटिक्स में क्रांति आएगी, जिससे मोबाइल उपकरणों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। उन्होंने आगे कहा, 'हम उन चुनिंदा कंपनियों में से एक हैं जो 2 मिलीवाट से कम क्षमता वाले चिप्स से लेकर पहनने योग्य स्मार्ट ईयरबड और डेटा सेंटर के लिए 2000 वाट क्षमता वाले चिप्स पर काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय बाजार में अपार संभावनाएं हैं, और भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन रहा है।

अगरतला में गृह मंत्री बोले- हिंदी और स्थानीय भाषाएं एक ही मां की दो बहनें; इनमें कोई टकराव नहीं

अगरतला। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर रहे। उन्होंने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक अहम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम हापनिया के इंटरनेशनल फेयर कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ, जिसमें इन क्षेत्रों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

क्या बोले गृह मंत्री?

सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के रिश्ते पर बड़ी बात कही। उन्होंने साफ किया कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच कभी कोई टकराव नहीं हो सकता। उन्होंने इन भाषाओं को 'एक ही मां की दो बहनें' बताया। शाह ने कहा कि हिंदी सभी भाषाओं की सहेली है। जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है, तो बाकी भारतीय भाषाएं भी अपने आप मजबूत होती हैं।

गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश अपनी भाषा को सीखने और अपनाने के संकल्प के साथ मजबूती से खड़ा है। इस सम्मेलन में राजभाषा नीति को लागू करने और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा हुई।

भाजपा के कामों कि की तारीफ

त्रिपुरा आने से पहले, दिन में अमित शाह ने असम के सिलचर में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम कांग्रेस पार्टी पचास साल के शासन में हासिल नहीं कर सकी, उसे भाजपा ने सिर्फ दस साल में पूरा कर दिखाया है।

उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में असम में बुनियादी ढांचे पर बहुत काम हुआ है। राज्य में हर रोज 14 किलोमीटर सड़क बनी है। इसके अलावा सैकड़ों पुलों का निर्माण पूरा किया गया और चार बड़े नए पुलों का उद्घाटन हुआ है। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया, लेकिन असम के विकास पर ध्यान नहीं दिया, जबकि भाजपा ने राज्य की तस्वीर बदल दी है।

पीएम मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले- 'अदृश्य राजनीतिक दबाव में हैं प्रधानमंत्री'

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में इस्तेमाल किए गए अपने जिउ-जित्सु के उदाहरण को समझाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक 'पकड़' और 'दबाव' में 'फंसे' हुए हैं, जो जनता को दिखाई नहीं देते। एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए गांधी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने संसद में अपने भाषण में जिउ-जित्सु का उदाहरण क्यों दिया। मैंने पकड़ और दबाव का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये जिउ-जित्सु खेल में होते हैं और इसी तरह प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में भी इसी तरह के तरीके मौजूद हैं, लेकिन जनता को दिखाई नहीं देते।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि राजनीतिक पकड़ और दबाव ज्यादातर छिपे रहते हैं। आम आदमी उन्हें देख नहीं पाता। और यह देखने के लिए कि दबाव कहां लगाया जा रहा है, आपको ध्यान से देखना होगा। गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दबावों के बीच 'फंसे' हुए हैं। अमेरिका में अडानी मामले और एपस्टीन मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि कई भारतीय नाम उन फाइलों से जुड़े हैं जिन्हें अभी तक जारी नहीं किया गया है।

गांधी ने कहा कि एक तरफ चीन हमारी सीमा पर बैठा है, और दूसरी तरफ अमेरिका। और हमारे प्रधानमंत्री इन दोनों के बीच फंसे हुए हैं। वे फँसे हुए हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि वित्तीय समर्थन से कायम है और उस छवि पर नियंत्रण भारत के बाहर के लोगों के हाथों में है। गांधी ने दावा किया कि नीतिगत फैसलों का असर किसानों और कपड़ा क्षेत्र पर पड़ सकता है, और आरोप लगाया कि भारत को अमेरिका से आयात बढ़ाना पड़ सकता है।

उन्होंने डेटा प्रबंधन पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डेटा है। तथ्य यह है कि हमारा डेटा नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका की अमेरिकी कंपनियों को मामूली कीमत पर सौंपा जा रहा है। और मेरी बात याद रखिए, हम डेटा कॉलोनी बनने जा रहे हैं। गांधी ने सवाल उठाया कि भारत अमेरिका के साथ डेटा, कृषि और उद्योग से संबंधित समझौते क्यों करेगा, और कहा कि इसका जवाब प्रधानमंत्री पर लगाए गए 'दबाव और दबाव' में निहित है।

तमिलनाडु विधानसभा में सीएम स्टालिन का बड़ा ऐलान, 'द्रविड़ मॉडल 2.0' तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले विश्वास जताते हुए कहा कि डीएमके सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटेगी। तमिलनाडु विधानसभा में आज अंतरिम बजट पर बहस के दौरान, स्टालिन ने अपनी सरकार के पांच साल के सफर पर विचार किया और भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो 'द्रविड़ मॉडल 2.0' सरकार बनाने जा रहे हैं, वह हमारी पिछली उपलब्धियों को भी पार कर जाएगी। हम फिर से जीतेंगे। हम फिर से सरकार बनाएंगे।

पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए स्टालिन ने कहा कि जब द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम ने सरकार बनाई थी, तब उन्हें खुशी और चिंता दोनों का अनुभव हुआ था। उन्होंने कहा कि जब हम जीते और सरकार बनाई, तो एक तरफ खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ चिंता भी थी। मैं सोच रहा था कि मैं इस जिम्मेदारी को कैसे निभाऊंगा। क्या मैं वादे पूरे कर पाऊंगा? क्या मैं जनता की इच्छा के अनुसार शासन कर पाऊंगा?

स्टालिन ने कहा कि सरकार ने पिछली सरकारों के कामकाज के कारण उत्पन्न गंभीर बाधाओं और उनके द्वारा वर्णित गैर-सहयोगी केंद्र सरकार के बीच कार्यभार संभाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, हम बहाने बनाकर निष्क्रिय नहीं बैठे, बल्कि कई योजनाओं को लागू किया।

उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन ने सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की दिशा में काम किया। पिछले पांच वर्षों में शुरू की गई प्रमुख पहलों को सूचीबद्ध करते हुए, उन्होंने विदियाल पयानम, कलाइग्नार मगलीर उरिमाई थिट्टम, नान मुधलवन, नाश्ता योजना, पुधुमाई पेन, सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन योजना, इनुयिर काप्पम और नम्मई काक्कुम 48 जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने 4,000 से अधिक मंदिरों के जीर्णोद्धार और अभिषेक का भी जिक्र किया। स्टालिन ने कहा कि इन पहलों से बच्चों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, बुनकरों, हाशिए पर रहने वाले समुदायों, आदि द्रविड़ और आदिवासी समूहों के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों को भी लाभ हुआ है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्या इसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूं? बिलकुल नहीं।

आईएमएफ प्रमुख ने कहा, 'भारत बेहद भाग्यशाली है कि उसके युवा अपना रहे हैं एआई'

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने शुक्रवार को कहा कि भारत बेहद भाग्यशाली है। उसके पास एक युवा आबादी है, जो एआई को अपना रही है। इसके साथ ही नीति निर्माता डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहे हैं और उद्यमिता में आने वाली बाधाओं को दूर कर रहे हैं।

जॉर्जीवा ने एआई को सकारात्मक यात्रा पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भी बधाई दी। उन्होंने यहां एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान पत्रकारों से कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी को एआई के लोकतंत्रीकरण के विषय को अपनाने के लिए धन्यवाद।' नीति निर्माताओं से एआई के संबंध में फुर्तीला रहने का आग्रह करते हुए। जॉर्जीवा ने कहा कि आईएमएफ एआई में क्या हो रहा है। इसे समझने और फिर भविष्य की नीतियों के लिए इसका अनुमान लगाने के लिए देशों के साथ काम करना जारी रखेगा।

सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश किया

उन्होंने कहा मैं यहां उपस्थित भारतीय मित्रों को एक संदेश देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके देश ने सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। इसलिए, एआई के लिए यह शर्त पूरी हो गई है। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपका देश उद्यमशीलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को सक्रिय रूप से दूर कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एआई को अपनाने से वैश्विक विकास में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि होगी।

बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की टीएमसी ने की तारीफ, भाजपा ने लगाया भ्रम फैलाने का आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी सियासी जंग शुक्रवार को और तेज हो गई। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इस प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता की बड़ी जीत बताया। वहीं भाजपा ने राज्य सरकार पर जमीनी स्तर पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई टीएमसी सरकार के बीच 'विश्वास की कमी' को उजागर करते हुए राज्य में विवादों से घिरी एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों को तैनात करने का एक 'असाधारण' निर्देश जारी किया।

टीएमसी बोली- ये जनता की बड़ी जीत

इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी ने दावा किया कि इससे एसआईआर अभियान में अनियमितताओं के उसके आरोपों की पुष्टि हुई है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि बंगाल की जनता के लिए एक बड़ी जीत। आज चुनाव आयोग के अहंकार का ऐतिहासिक रूप से पर्दाफाश हुआ है।

टीएमसी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची निरीक्षक वैध दावों को नजरअंदाज कर रहे थे और वैध मतदाताओं को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश देकर 'करारा प्रहार' किया है कि सभी दावों, आपत्तियों और विसंगति के मामलों को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त निष्पक्ष न्यायिक अधिकारियों द्वारा निपटाया जाए।

कोंकण में आम पर प्राकृतिक आपदा को लेकर सकारात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें– संरक्षक मंत्री नितेश राणे के निर्देश

दिव्यांश

मुंबई, दिनांक 20: नवंबर माह के प्रारंभ में हुई वर्षा के कारण सिंधुदुर्ग जिले में आम के वृक्षों पर समय पर बौर नहीं आ सका। इसके बाद दिसंबर माह से जिले में लगातार कम तापमान और ठंडे मौसम के कारण आम के वृक्षों पर अच्छी तरह बौर आया। वर्तमान में तीसरी बार बौर आने के बाद भी इससे आम उत्पादक किसानों को कितनी आय प्राप्त होगी, इसका आकलन करना संभव नहीं है। अतः कृषि विभाग द्वारा उचित एवं विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर तत्काल शासन को प्रस्तुत किया जाए, ऐसे निर्देश मत्स्य, बंदरगाह एवं सिंधुदुर्ग जिले के संरक्षक मंत्री नितेश राणे ने दिए।

सिंधुदुर्ग जिले में आम की फसल पर रोगों के कारण हुए नुकसान को लेकर त्वरित उपायों पर चर्चा हेतु मंत्रालय में संरक्षक मंत्री नितेश राणे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिंधुदुर्ग की जिलाधिकारी तृप्ति धोडामिसे, डॉ. बाबासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ के कुलपति संजय भवे, उद्यानिकी संचालक अंकुश माने, कोंकण कृषि विद्यापीठ के अनुसंधान संचालक डॉ. वी. यू. शहारे, पादप रोग विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. पुष्पा पाटिल, कीट विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विजय देसाई, कृषि विभाग के अवर सचिव डॉ. ललित कुमार धायगुडे, साथ ही आम एवं अन्य फल बागायतदार किसान संघ तथा आम बागायतदार एवं व्यापारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

कोंकण क्षेत्र में आम की फसल पर बौर न आने के कारण आम उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही, यदि भविष्य में वर्षा होती है अथवा तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है, तो आम उत्पादक किसानों के लिए स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। इस संदर्भ में मंत्री श्री राणे ने आश्वासन दिया कि इस स्थिति को प्राकृतिक आपदा घोषित कर कोंकण के आम उत्पादक किसानों को शासन की ओर से व्यापक सहायता प्रदान की जाएगी।

आम की फसल पर विभिन्न कीटनाशकों के छिड़काव से उत्पादन में कमी आती है। इस विषय में एक ठोस नीति तैयार करने की आवश्यकता पर भी संरक्षक मंत्री राणे ने बल दिया। उन्होंने कृषि विद्यापीठों को और अधिक सक्षम बनाने पर विशेष जोर दिया। साथ ही, कोंकण में आम उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के प्रति भी उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया।

छत्रपति संभाजीनगर में 'हमारा संविधान - हमारा गौरव' पहल के अंतर्गत डिजिटल रथों को मिला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

दिव्यांश

मुंबई। स्वतंत्रता के पश्चात देश का संविधान लागू हुए इस वर्ष 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य शासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा 'संविधान अमृत महोत्सव' के अंतर्गत 'हमारा संविधान - हमारा गौरव' नामक विशेष जनजागरण अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत तैयार किए गए संविधान जनजागरण डिजिटल रथ का हाल ही में मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों उद्घाटन किया गया।

इस अभियान का हिस्सा रहे संविधान जनजागरण डिजिटल रथ छत्रपति संभाजीनगर शहर में विभिन्न शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण कर रहा है। इस दौरान विद्यालय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी जा रही है तथा नागरिकों की ओर से भी इस रथ को उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिल रहा है।

सांस्कृतिक कार्य मंत्री अधिवक्ता आशीष शेलार की संकल्पना से साकार हुए इस डिजिटल रथ के माध्यम से भारतीय संविधान की निर्मिति प्रक्रिया, संविधान सभा की भूमिका, नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार एवं कर्तव्यों की प्रभावी जानकारी दी जा रही है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार सहित संविधान की महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाई जा रही है। यह जनजागरण अभियान लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व, समाज में संविधान के स्थान तथा नागरिकों के कर्तव्यों के संबंध में प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। इस पहल के माध्यम से नागरिकों में संविधान के प्रति गौरव की भावना और अधिक सुदृढ़ हो रही है। विशेष रूप से विद्यार्थियों एवं युवा पीढ़ी में संविधान के प्रति सम्मान, कर्तव्यबोध तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

होली के अवसर पर मनरेगा श्रमिकों के लिए 67 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत– रोजगार गारंटी योजना मंत्री भारत गोगावले

मुंबई। होली के अवसर पर आदिवासी श्रमिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को तत्काल मजदूरी भुगतान हेतु 67 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की है। उक्त निधि का भुगतान कोषागार को प्रस्तुत कर दिया गया है तथा आगामी दो से तीन दिनों में श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी की राशि सीधे जमा की जाएगी, यह जानकारी रोजगार गारंटी योजना विभाग के मंत्री भारत गोगावले ने दी।

मंत्री भारत गोगावले ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मेलघाट, पालघर एवं अन्य आदिवासी बहुल जिलों में श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराते समय श्रम बजट बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र शासन के पास लंबित था, जिसके कारण कुछ समय से मजदूरी भुगतान रुका हुआ था। इस पृष्ठभूमि में राज्य शासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि 19 फरवरी 2026 को केंद्र शासन ने राज्य के 13 करोड़ मानव-दिवस के श्रम बजट को बढ़ाकर 16 करोड़ मानव-दिवस का संशोधित बजट स्वीकृत किया है। इसके परिणामस्वरूप मार्च माह के अंत तक श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध होगा तथा मजदूरी का भुगतान समय पर किया जा सकेगा।

मध्य रेल के मुंबई मंडल पर रविवार को मेगा ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल, मुंबई मंडल दिनांक 22.02.2026 को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर मेगा ब्लॉक परिचालित करेगा, जो इस प्रकार हैः

मेन लाइन

मुलुंड और ठाणे स्टेशनों के बीच अप और डाउन स्लो लाइन 11:00 बजे से 16:00 बजे तक

सीएसएमटी से 10:04 बजे से 15:09 बजे तक चलने वाली डाउन स्लो सेवाएं मुलुंड और ठाणे स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और ठाणे स्टेशन पर डाउन स्लो लाइन पर पुनः डायवर्ट की जाएंगी, जिससे वे अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी।

कल्याण से सुबह 10:36 बजे से दोपहर 15:24 बजे तक की अप स्लो ट्रेन सेवाएं ठाणे और मुलुंड स्टेशनों के बीच अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और मुलुंड स्टेशन पर अप स्लो लाइन पर पुनः डायवर्ट की जाएंगी, जिससे वे अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी।

मुंबई के सीएसएमटी से सुबह 11:00 बजे से शाम 17:00 बजे के बीच चलने वाली अप और डाउन की सभी स्लो ट्रेन सेवाएं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी।

हार्बर लाइन

पनवेल और वाशी स्टेशनों के बीच हार्बर लाइन (पोर्ट लाइन को छोड़कर) सुबह 11:05 बजे से शाम 16:05 बजे तक (अप और डाउन)

हार्बर लाइन खंड पर

पनवेल से सुबह 10:33 बजे से दोपहर 15:49 बजे तक सीएसएमटी की ओर जाने वाली हार्बर लाइन की अप सेवाएं और सीएसएमटी से सुबह 9:45 बजे से दोपहर 15:12 बजे तक बेलापुर/पनवेल की ओर जाने वाली हार्बर लाइन की डाउन सेवाएं रद्द रहेंगी।

ट्रांस हार्बर लाइन खंड पर पनवेल से 11:02 बजे से 15:53 बजे तक ठाणे की ओर जाने वाली ट्रांस हार्बर लाइन की अप सेवाएं और ठाणे से सुबह 10:01 बजे से दोपहर 15:20 बजे तक पनवेल की ओर जाने वाली ट्रांस हार्बर लाइन की डाउन सेवाएं रद्द रहेंगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान सीएसएमटी मुंबई-वाशी खंड पर विशेष लोकल ट्रेन सेवाएं चलाई जाएंगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान ठाणे-वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान पोर्ट लाइन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

बुनियादी ढांचे के रखरखाव और संरक्षा के लिए ये मेगा ब्लॉक आवश्यक हैं। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है।

फ्रेट लोडिंग को गतिशील बनाने के क्रम में DRM राजू भडके द्वारा उएइण का निरीक्षण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

माल ढुलाई को और अधिक सशक्त एवं गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा आज, दिनांक 20 फरवरी, 2026 को Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (जीएसएफसी), बाजवा साइडिंग का दौरा किया गया। उनके इस निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रिनी भी उपस्थित थीं।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने निरीक्षण के दौरान रेल संपर्क, माल ढुलाई अवसंरचना तथा Indian Railways और उर्वरक उद्योग के मध्य समन्वय की समीक्षा की, जिससे देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरकों का समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित किया जा सके।

मंडल रेल प्रबंधक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसएफसी के माल लदान प्रदर्शन की भी समीक्षा की तथा जीएसएफएसी-बाजवा साइडिंग पर अब तक के सर्वाधिक 54 रेक के मासिक लदान की उपलब्धि पर संगठन को बधाई दी। उन्होंने रेलवे एवं जीएसएफसी टीमों द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों की सराहना की।

भडके ने लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने, स्वचालन (ऑटोमेशन) के प्रभावी उपयोग तथा परिचालन योजना में सुधार के माध्यम से माल की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने वर्तमान 1.5 रेक प्रतिदिन की लोडिंग क्षमता को बढ़ाकर 2 रेक प्रतिदिन करने की सलाह दी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला और अधिक सुदृढ़ हो सके।

इस अवसर पर जीएसएफसी के कार्यकारी निदेशक संजीव वर्मा ने कंपनी की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया तथा वडोदरा मंडल द्वारा समय पर खाली रेक उपलब्ध कराने हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप कंपनी अपनी लगभग 92 प्रतिशत उत्पादन सामग्री का परिवहन रेल मार्ग से कर सकी।

पश्चिम रेलवे कुशल माल परिवहन व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। रेलवे और उर्वरक निर्माताओं के बीच सतत समन्वय से देशभर के किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

रविवार को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं

पश्चिम रेलवे का वसई रोड एवं विरार स्टेशनों के बीच रात्रिकालीन ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेलपथ, सिगनलिंग तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा वसई रोड एवं विरार स्टेशनों के बीच शनिवार/रविवार अर्थात 21/22 फरवरी, 2026 की मध्यरात्रि के दौरान अप एवं डाउन धीमी लाइनों पर 00.15 बजे से 04.15 बजे तक चार घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बोरीवली एवं दहिसर स्टेशनों के बीच सभी लाइनों पर 02.10 बजे से 04.10 बजे तक नए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के गर्डर लॉन्चिंग हेतु एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान धीमी लाइनों की सभी उपनगरीय ट्रेनों को वसई रोड एवं विरार

स्टेशनों के बीच फास्ट लाइनों पर चलाया जाएगा। बोरीवली एवं दहिसर के बीच एफओबी के गर्डर लॉन्चिंग कार्य के कारण कुछ उपनगरीय तथा मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

रेगुलेट होने वाली ट्रेनेंः

1) ट्रेन संख्या 19038 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस को विरार एवं भायंदर स्टेशनों के बीच 01 घंटा रेगुलेट होगी।

2) ट्रेन संख्या 22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल को विरार एवं भायंदर स्टेशनों के बीच 45 मिनट रेगुलेट होगी।

3) ट्रेन संख्या 22904 भुज-बांद्रा टर्मिनस एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को सूरत एवं विरार स्टेशनों के बीच 20 मिनट रेगुलेट होगी। 4) ट्रेन संख्या 90006 विरार-चर्चगेट लोकल, जो विरार से 03.25 बजे प्रस्थान करती है, को विरार से 15 मिनट विलंब से चलाया जाएगा। 5) ट्रेन संख्या 90018 विरार-चर्चगेट लोकल, जो विरार से 03.40 बजे प्रस्थान करती है, को विरार से 15 मिनट विलंब से चलाया जाएगा। ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है।

इसलिए, पश्चिम रेलवे उपनगरीय खंड पर रविवार, 22 फरवरी, 2026 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

बोईसर-पालघर स्टेशनों के बीच ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बोईसर और पालघर स्टेशनों के बीच आर.एच. गर्डर लॉन्च करने के कार्य के लिए 21/22 फरवरी तथा 22/23 फरवरी, 2026 की मध्यरात्रि में ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 21/22 फरवरी, 2026 की मध्यरात्रि में अप एवं डाउन लाइनों पर 23:15 बजे से 02:45 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा। इसी प्रकार 22/23 फरवरी, 2026 की मध्यरात्रि में डाउन लाइन पर 02:10 बजे से 05:25 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा।

इन ब्लॉकों के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः-

21 फरवरी, 2026 को निरस्त रहने

वाली ट्रेनेंः-

1.ट्रेन संख्या 93039 विरार - दहानू रोड लोकल, जो विरार से 21:20 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।

2.ट्रेन संख्या 93042 दहानू रोड - विरार लोकल, जो दहानू रोड से 22:45 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।

रेगुलेट की जाने वाली ट्रेनेंः-

1.ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस - बरौनी एक्सप्रेस, जो 21 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट होगी।

2.ट्रेन संख्या 69173 विरार - दहानू रोड मेमू, जो 21 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट होगी।

3.ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली - नंदुरबार एक्सप्रेस, जो 21 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 25 मिनट रेगुलेट होगी।

4.ट्रेन संख्या 12298 पुणे - अहमदाबाद एक्सप्रेस, जो 21 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 1 घंटा रेगुलेट होगी।

5.ट्रेन संख्या 22923 बांद्रा टर्मिनस - जामनगर एक्सप्रेस, जो 21 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 50 मिनट रेगुलेट होगी।

6.ट्रेन संख्या 19003 दादर - भुसावल एक्सप्रेस, जो 22 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 40 मिनट रेगुलेट होगी।

7.ट्रेन संख्या 19019 बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार एक्सप्रेस, जो 22 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 40 मिनट रेगुलेट होगी।

मनपा शिक्षा विभाग द्वादा आरटीई आनलाइन आवेदन करने के लिए लोगो से आव्हान

मंत्र भारत। भाईदंर

एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए, बच्चों के मुफ़्त और ज़रूरी शिक्षा के अधिकार एक्ट के 2009 के सेक्शन 12 (C) (1) के मुताबिक, सेल्फ़-एडेड स्कूलों और अनएडेड स्कूलों में कमज़ोर तबके के बच्चों के लिए RTE 25% एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन लागू किया जा रहा है। RTE 25% ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के तहत एलिजिबल स्कूलों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुल 79 स्कूल हैं। RTE 25% ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के लिए बच्चों के पेरेंट्स से ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने के लिए 17/02/2026 से 10/03/2026 तक वेबसाइट https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मनपा द्वारा ज्यादा से ज़्यादा अभिभावको से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की अपील की गयी है।

पश्चिम रेलवे द्वारा साप्ताहिक होली विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी

ट्रेन संख्या	प्रारंभिक स्टेशन एवं गंतव्य	सेवा की तिथियाँ	प्रस्थान	आगमन
09075	मुंबई सेंट्रल - काठगोदाम (सुपरफास्ट)	25.02.2026 to 25.03.2026	10:55 hrs बुधवार	14:30 hrs (अगले दिन)
09076	काठगोदाम - मुंबई सेंट्रल (सुपरफास्ट)	26.02.2026 to 26.03.2026	17:30 hrs (गुरूवार)	21:00 hrs (अगले दिन)
ठहरावः बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, भरतपुर, अछनेरा, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बदायूं, बरेली जंक्शन, बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेरी, किच्छा, लालकुआँ तथा हल्द्वानी स्टेशन (दोनों दिशाओं में)।				
संरचनाः एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच।				
09185	मुंबई सेंट्रल - कानपुर अनवरगंज (सुपरफास्ट)	22.02.2026 to 29.03.2026	10:55 hrs (रविवार)	15:35 hrs (अगले दिन)
09186	कानपुर अनवरगंज - मुंबई सेंट्रल (सुपरफास्ट)	23.02.2026 to 30.03.2026	18:25 hrs (सोमवार)	22:30 hrs (अगले दिन)
ठहराव : बोरीवली, वापी, वलसाड, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा जंक्शन, मथुरा कैंट, हाथरस सिटी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज एवं बिल्हौर स्टेशन (दोनों दिशाओं में)। (अतिरिक्त रूप से, ट्रेन संख्या 09185 सूरत स्टेशन पर भी रुकेगी।)				
संरचना : एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच।				
09023	बांद्रा टर्मिनस - पालिताना	27.02.2026	21:45 hrs (शुक्रवार)	12:00 hrs (अगले दिन)
09024	पालिताना - बांद्रा टर्मिनस	01.03.2026	20:00 hrs (रविवार)	12:00 hrs (अगले दिन)
ठहराव : बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, बोटाद, ढोला, सोंगढ़ तथा सिहोर गुजरात स्टेशन (दोनों दिशाओं में)।				
संरचना : एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच।				

ठहराव, ठहरने का समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएँ।

ट्रेन संख्या 09075, 09185, 09023 एवं 09024 के लिए बुकिंग 21.02.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। उपरोक्त ट्रेनें विशेष किराए पर विशेष ट्रेन के रूप में संचालित की जाएंगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in

Like us & Follow us on:
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ लेकर चलें।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र के विकास हेतु विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में महाराष्ट्र के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस शिखर सम्मेलन में सहभाग लिया तथा कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर संबोधन किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों से भेंट की, बैठकों में भाग लिया तथा अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही 'कुंभदूत' नामक अनुप्रयोग का भी अनावरण किया गया।

आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए 'शिक्षासाथी'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओपन एआई के सार्वजनिक नीति प्रमुख क्रिस लेहन तथा रॉकेट लर्निंग के अज़ीज़ गुप्ता से भेंट की। इस दौरान राज्य की आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित 'शिक्षासाथी' उपकरण प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ओपन एआई एवं रॉकेट लर्निंग के साथ साझेदारी करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है। इस पहल से लाखों आंगनवाड़ी सेविकाओं को लाभ होगा।

भारतजेन प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान के साथ समझौता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति

में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारतजेन प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान के मध्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रशासनिक प्रणालियों के डिजिटलीकरण से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के अंतर्गत सूचना का आदान-प्रदान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, प्रायोगिक परियोजनाएँ तथा उभरते कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सर्वन एआई के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विकास हेतु साझेदारी

महाराष्ट्र शासन एवं सर्वन एआई के मध्य आशय पत्र का आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा डॉ. प्रत्युष कुमार उपस्थित थे। इस सहयोग का उद्देश्य महाराष्ट्र में व्यावहारिक क्रियान्वयन हेतु समग्र एवं स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधोसंरचना का निर्माण करना है।

इस साझेदारी के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावी उपयोग की सुदृढ़ नींव रखी जाएगी। साथ ही कौशल विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान, नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को गति दी जाएगी। आगामी अवधि में 20 मेगावाट की कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुकूल संगणन क्षमता विकसित करने तथा भविष्य में इसे 50 मेगावाट तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल महाराष्ट्र की डिजिटल संप्रभुता को सशक्त बनाएगी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। इस अवसर पर मंत्री अधिवक्ता आशीष शेलार तथा सर्वन एआई के संस्थापक डॉ. प्रत्युष कुमार उपस्थित थे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शासन के लिए महाराष्ट्र शासन एवं ओपन एआई के बीच सहयोग

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र शासन एवं ओपन एआई के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। यह सहयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शासन एवं नवाचार के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस साझेदारी के माध्यम से नागरिकों को अधिक स्मार्ट, समावेशी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता समर्थित सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

इस सहयोग के अंतर्गत शासकीय परियोजनाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी तथा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायपालिका, सूचना प्रौद्योगिकी तथा शहरी एवं ग्रामीण विकास जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में 12 कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान विकसित कर प्रायोगिक रूप से लागू किए जाएँगे। प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार के लिए 'महा ओपन स्पेस प्रयोगशाला' के रूप में भौतिक सुविधाओं की भी संभावना तलाशी जाएगी। कार्यशालाओं, नवाचार प्रतियोगिताओं तथा विशेषज्ञ सम्मेलनों के माध्यम से महाराष्ट्र के कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सतत संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। नागरिकों को बड़े स्तर पर अधिक प्रभावी एवं सुविधाजनक सेवाएँ प्रदान करने के लिए चैट जीपीटी की उन्नत क्षमताओं का उपयोग कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम अनुप्रयोग अथवा वेबसाइट विकसित की जाएँगी।

विविध बैठकों का आयोजन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्व बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष योहान्स जुट से भेंट कर कृषि क्षेत्र में परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवा वितरण प्रणाली, रोजगार सृजन तथा युवाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिंगापुर के डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री जोस्पिन टेओ से भी भेंट कर डिजिटल शासन पर विचार-विमर्श किया।

महाराष्ट्र शासन की चार वर्षीय अवधि के लिए 1,500 करोड़ रुपये के बांड जारी किए जाएंगे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र शासन द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए 1,500 करोड़ रुपये मूल्य के बांड जारी किए जाएंगे। इन बांडों की बिक्री शासन की संशोधित अधिसूचना में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार की जाएगी। इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग शासन के विकास कार्यों के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा, यह जानकारी वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता ने एक निवेदन के माध्यम से दी।

गैर-प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी पद्धति (संशोधित) के अनुसार, शासन ऋण प्रतिभूतियों की कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत भाग पात्र व्यक्तिगत एवं संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। तथापि, किसी एक निवेशक को कुल अधिसूचित राशि के अधिकतम 1 प्रतिशत तक ही आवंटन किया जाएगा।

यह नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय में 24 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। नीलामी हेतु निविदाएँ 24 फरवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक की संगणकीय प्रणाली, कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जाएँगी।

ई-कुबेर प्रणाली के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएँ प्रातःकाल संगणकीय प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जाएँगी। प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएँ प्रातः 10.30 बजे से 11.30 बजे तक तथा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएँ प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। नीलामी के परिणाम उसी दिन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएँगे। सफल निविदादाताओं द्वारा राशि का भुगतान 25 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

भुगतान नकद, बैंकर चेक, भुगतान आदेश, मांग पत्र अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई स्थित उनके खाते से देय चेक के माध्यम से किया जाएगा। यह अग्रिम भुगतान बैंकिंग कार्य समय की समाप्ति से पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा।

बांड की अवधि चार वर्ष की होगी तथा बांड की परिपक्वता तिथि 25 फरवरी 2026 होगी। यह ऋण पूर्ण रूप से 25 फरवरी 2030 को चुकता किया जाएगा। बांड पर वार्षिक एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। बांड के मूल निर्गम दिनांक से मूलधन पर ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष किया जाएगा। ब्याज का भुगतान 25 अगस्त एवं 25 फरवरी को अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

आदिवासी आश्रम शालाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा

अधोसंरचना पर विशेष जोर योजनाओं और लाभार्थियों को केंद्र में रखकर निधि व्यय की जाए – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य के आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आश्रम शालाओं की गुणवत्ता में विशेष सुधार किया जाएगा। आश्रम शालाओं में मरम्मत, स्वच्छता, सुरक्षा तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के कार्य तत्काल किए जाएँ। आदिवासी विकास विभाग की निधि का उपयोग सीधे लाभार्थियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ऐसा प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने किया।

जिला वार्षिक आदिवासी उपघटक कार्यक्रम 2026-27 की प्रारूप योजना तैयार करने के लिए मुंबई में आयोजित बैठक की अध्यक्षता आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने की। इस बैठक में वन मंत्री एवं पालघर जिले के संरक्षक मंत्री गणेश नाईक, जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री तथा जलगांव जिले के संरक्षक मंत्री गुलाबराव पाटिल, विद्यालय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, आदिवासी विकास विभाग के कार्यवाहक आयुक्त गोपीचंद कदम, जनप्रतिनिधि, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा परियोजना अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली के माध्यम से उपस्थित थे।

मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने कहा कि प्रत्येक आश्रम शाला में सुसज्जित ग्रंथालय तथा पृथक अध्ययन कक्ष अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक साधन, डिजिटल सुविधाएँ तथा गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जाएगा।

रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। आदिवासी महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार सृजन करने वाली उद्यमी बनें, इस दिशा में प्रयास किए जाएँगे।

बैठक में आदिवासी जिलों में आदिवासी देवताओं के तीर्थस्थलों के विकास हेतु पृथक निधि उपलब्ध कराने के विषय पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। जिन जिलों में सांस्कृतिक भवनों के निर्माण की माँग है, वे आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ठक्कर बप्पा आदिवासी बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी बस्तियों के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बस्तियों में बुनियादी सुविधाएँ विकसित की जाएँगी, ऐसा मंत्री वुइके ने बताया।

प्रत्येक जिले में कम से कम एक आश्रम शाला का चयन कर उसे अत्याधुनिक सुविधाएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आदर्श प्रबंधन के मापदंडों के आधार पर 'आदर्श आश्रम शाला' के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही 'प्रधानमंत्री जनमन योजना' तथा 'धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान' जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को जिला स्तर पर प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से लागू किया जाए। इस बैठक में पालघर, नाशिक, नंदुरबार, यवतमाल, चंद्रपुर, ठाणे, जलगांव, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, हिंगोली, परभणी, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, छत्रपति संभाजीनगर, लातूर, जालना, बीड, सोलापुर, धाराशिव, मुंबई शहर तथा मुंबई उपनगर जिलों के जिला वार्षिक आदिवासी उपघटक कार्यक्रम की समीक्षा की गई।

'डीपीडीपी' कानून के तहत नागरिकों के पास ही डेटा संरक्षण के अधिकार– प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

लोक प्रशासन संस्थान के प्रशिक्षण वर्ग में 'डीपीडीपी' कानून पर मार्गदर्शन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कानून, 2023 नागरिक-केंद्रित है। इस कानून के अंतर्गत नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा तथा संबंधित नागरिक की सहमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस कानून से प्रत्येक नागरिक की डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित होगा और व्यावसायिक उद्देश्यों से इस जानकारी के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, ऐसा विश्वास सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के प्रधान सचिव एवं महानिदेशक ब्रिजेश सिंह ने व्यक्त किया।

मंत्रालय के परिषद सभागार में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की ओर से आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून, 2023 तथा शासकीय अधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ' विषय पर प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह मार्गदर्शन कर रहे थे। इस अवसर पर मंच पर लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय तथा मानद कोषाध्यक्ष विनायक देवधर उपस्थित थे।

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह ने कहा कि वर्तमान में साइबर अपराध के माध्यम से बनी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। इस अर्थव्यवस्था का आकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से भी दोगुना है। इससे साइबर अपराध के जरिए होने वाले लेन-देन की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नए डीपीडीपी कानून के कारण नागरिकों की जानकारी सुरक्षित रहेगी, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जानकारी का उपयोग संभव नहीं होगा। हालांकि, शासन लोककल्याणकारी उद्देश्यों से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जानकारी का उपयोग कर सकता है।

डीपीडीपी कानून मई 2027 से लागू होगा। इससे पहले कानून में दी गई धाराओं के अनुसार विभागों को विभिन्न कार्यान्वयन तंत्र विकसित करने के लिए समय दिया गया है। कानून लागू होने के बाद किसी भी योजना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित तंत्रों की होगी। किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया, ई-मेल आदि के माध्यम से भेजी नहीं जा सकेगी। 'डेटा ब्रीच' होने की स्थिति में संबंधित को जुर्माना भरना होगा। व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की जा सकेगी, लेकिन समेकित जानकारी आंकड़ों के रूप में दी जा सकेगी–यह जानकारी भी प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह ने दी।

उन्होंने आगे बताया कि इस कानून के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से पहले संबंधित नागरिक को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। नागरिक की सहमति प्राप्त करने के बाद ही जानकारी का उपयोग किया जा सकेगा। जिस उद्देश्य से जानकारी प्राप्त की गई है, उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य, नागरिक की पसंद एवं सहमति तथा जानकारी संग्रहण की सीमाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी।

प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया और उनके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह द्वारा किया गया। साथ ही प्रशिक्षण सत्र के अंत में कानून पर आधारित प्रश्नावली प्रस्तुत कर उसके उत्तर लिए गए। प्रशिक्षण सत्र संवादात्मक स्वरूप में संपन्न हुआ। अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय ने प्रशिक्षण वर्ग पर संतोष व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया। प्रशिक्षण वर्ग में अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रभावी आंकड़ा प्रबंधन से शासन अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं नागरिक-केंद्रित बनता है– सुमनेश जोशी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के उप महानिदेशक सुमनेश जोशी ने कहा कि डिजिटल युग में आंकड़े ही वास्तविक शक्ति हैं और प्रभावी आंकड़ा प्रबंधन से शासन अधिक पारदर्शी, तेज तथा नागरिकोन्मुखी बनता है।

वे महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों के लिए आयोजित 'डिजिटल शासन को सरल बनाना – प्रत्येक कार्यालय को क्या जानना आवश्यक है' विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मेलन सभागार में संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय, मानद कोषाध्यक्ष विकास देवधर तथा विशेष कार्य अधिकारी शशांक यशवंत बारवे उपस्थित थे।

सुमनेश जोशी ने कहा कि प्रशासन अब कागजी फाइलों के स्थान पर डिजिटल कार्यप्रणाली की ओर अग्रसर हो गया है। रजिस्टरों के स्थान पर डैशबोर्ड तथा विलंब के स्थान पर वास्तविक समय निगरानी प्रणाली अपनाई जा रही है।

उन्होंने आंकड़ों की संरचना, सटीक आंकड़ा संकलन, कागजरहित कार्यप्रणाली तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना की तुलना एक डिजिटल राजमार्ग से की तथा आधार एवं एम-आधार अनुप्रयोग के माध्यम से आंकड़ों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसकी जानकारी दी। साथ ही, साइबर सुरक्षा के लिए 'संचार साथी' पोर्टल का उपयोग करने का भी आह्वान किया।

जोशी ने कहा कि भविष्य में यदि डिजिटल शासन से संबंधित किसी भी प्रकार के नए प्रश्न, शंकाएँ अथवा समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, तो प्रशिक्षणार्थी तथा शासकीय अधिकारी या कर्मचारी किसी भी समय दूरभाष अथवा ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

'डीपीडीपी' कानून के अंतर्गत नागरिकों को डेटा संरक्षण का अधिकार– प्रधान सचिव बृजेश सिंह

लोक प्रशासन संस्थान के प्रशिक्षण वर्ग में 'डीपीडीपी' कानून पर मार्गदर्शन

मुंबई। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून, 2023 नागरिक-केंद्रित है। इस कानून के अंतर्गत नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा तथा संबंधित नागरिक की सहमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय के प्रधान सचिव एवं महासंचालक बृजेश सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून प्रत्येक नागरिक की डिजिटल जानकारी का व्यक्तिगत स्तर पर संरक्षण करेगा तथा व्यावसायिक उद्देश्यों से इस जानकारी के उपयोग पर रोक लगाएगा।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा मंत्रालय के सम्मेलन सभागार में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून, 2023 तथा शासकीय अधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ' विषय पर प्रधान सचिव बृजेश सिंह मार्गदर्शन कर रहे थे। इस अवसर पर लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय तथा मानद कोषाध्यक्ष विनायक देवधर मंचासीन थे।

प्रधान सचिव बृजेश सिंह ने कहा कि वर्तमान में विश्व में साइबर अपराध के माध्यम से निर्मित अर्थव्यवस्था अत्यंत विशाल है। इस अर्थव्यवस्था का आकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद से दोगुना है। इससे साइबर अपराध के माध्यम से होने वाले लेन-देन की व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकता है। नए डीपीडीपी कानून के कारण नागरिकों की जानकारी सुरक्षित रहेगी, इसलिए इस जानकारी का व्यावसायिक उपयोग संभव नहीं होगा। हालांकि, शासन लोककल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जानकारी का उपयोग कर सकेगा।

डीपीडीपी कानून मई 2027 से लागू होगा। इससे पूर्व कानून की धाराओं के अनुसार विभागों को विभिन्न क्रियान्वयन तंत्र विकसित करने के लिए समय प्रदान किया गया है। कानून लागू होने के पश्चात किसी भी योजना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित तंत्रों की होगी। किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी विभिन्न सामाजिक माध्यमों, ई-मेल आदि के माध्यम से भेजी नहीं जा सकेगी। यदि 'डेटा उल्लंघन' होता है, तो संबंधित को दंड भरना होगा। व्यक्तिगत जानकारी प्रदान नहीं की जा सकेगी, किंतु समेकित जानकारी आँकड़ों के रूप में उपलब्ध कराई जा सकेगी, यह जानकारी भी प्रधान सचिव बृजेश सिंह ने दी।

उन्होंने आगे बताया कि इस कानून के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पूर्व संबंधित नागरिक को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। नागरिक की सहमति प्राप्त करने के बाद ही जानकारी का उपयोग किया जा सकेगा। जिस उद्देश्य से जानकारी एकत्र की गई है, उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। इसके लिए जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य, नागरिक की पसंद एवं सहमति तथा जानकारी संग्रह की सीमाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी।

प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया तथा उनके प्रश्नों के समाधान का प्रयास प्रधान सचिव बृजेश सिंह द्वारा किया गया। प्रशिक्षण सत्र के अंत में कानून पर आधारित प्रश्नावली प्रस्तुत कर उसके उत्तर लिए गए। संपूर्ण प्रशिक्षण सत्र संवादात्मक स्वरूप में संपन्न हुआ। अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय ने प्रशिक्षण वर्ग पर संतोष व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया। प्रशिक्षण वर्ग में अधिकारीगण उपस्थित थे।

कारोबारी राज कुंद्रा को 150 करोड़ रुपये के बिटकॉइन घोटाले के मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली

मुंबई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने कथित 150 करोड़ रुपये के बिटकॉइन 'पोंजी' घोटाले के मामले में जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच में शामिल 18 आरोपियों में से एक कुंद्रा पिछले महीने दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने पर जमानत दे दी और निर्देश दिया कि विदेश यात्रा से पहले उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। अदालत कक्ष के बाहर संक्षिप्त बातचीत में कुंद्रा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन उन्होंने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मुझे घर पर बोलने नहीं देती और मेरे वकील मुझे

अदालत में बोलने नहीं देते।

विशेष अदालत ने इससे पहले ईडी की आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए कुंद्रा और दुबई स्थित कारोबारी राजेश सतीजा को समन जारी किया था। दोनों को 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। कुंद्रा और सतीजा को पिछले साल सितंबर में दायर पूरक आरोपपत्र में आरोपी के रूप में जोड़ा गया था। जांच के दौरान कुंद्रा को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और अदालत के संज्ञान के बाद उन्हें औपचारिक रूप से जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा। ईडी के अनुसार, कुंद्रा ने कथित तौर पर गेन बिटकॉइन घोटाले के 'मास्टरमाइंड' अमित भारद्वाज से 6.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे, जिन्हें यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए 285 बिटकॉइन में परिवर्तित किया गया था, जिसे कथित तौर पर एक इजरायली नागरिक को प्राप्त किया जाना था। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि 2018 से कई मौके दिए जाने के बावजूद कुंद्रा बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए वॉलेट पते उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया कि ईडी का मूल्यांकन कानूनी रूप से मान्य नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि एजेंसी ने जुलाई 2017 में 285 बिटकॉइन का मूल्य लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 6.6 करोड़ रुपये) आंका था, लेकिन बाद में 16 अप्रैल, 2024 के लगभग 52 लाख रुपये प्रति बिटकॉइन के मूल्यांकन को अपनाकर लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि पर पहुंच गई।

सम्पादकीय

फ्रांस से 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी', क्या भारत की ताकत अब व्यापार से रक्षा तक बदलेगी समीकरण

बदलते दौर में भू-राजनीतिक उथल-पुथल और अनिश्चितताओं के बीच भारत आर्थिक एवं रणनीतिक स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ साझेदारी को और व्यापक बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों के बाद भारत ने अब फ्रांस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' में बदल दिया है। इसके तहत दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है।

नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच मंगलवार को मुंबई में हुई वार्ता के दौरान बनी सहमति के बाद इक्कीस समझौतों को स्वीकृति दी गई। इस साझेदारी को वैश्विक स्थिरता और रणनीतिक दृष्टिकोण से कई मायनों में महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल द्विपक्षीय व्यापार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि रक्षा के मोर्चे पर भी भारत की स्थिति मजबूत होगी।

पिछले दिनों भारत ने ब्रिटेन और ओमान के साथ व्यापार समझौते किए थे। उसके बाद न्यूजीलैंड और फिर यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया। हाल में भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का एलान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने भारत पर लगाए गए पचास फीसद शुल्क को घटाकर अठारह फीसद कर दिया। इसमें दोराय नहीं कि अमेरिका की ओर से भारत पर भारी-भरकम शुल्क लगाए जाने के बाद देश का निर्यात कारोबार प्रभावित हुआ।

इस संकट से निपटने के लिए भारत ने अपने उत्पादों के वास्ते दुनिया के विभिन्न देशों में वैकल्पिक बाजार तलाशने की हरसंभव कोशिश की तथा व्यापार समझौतों की शक्ल में उसके सफल नतीजे भी सामने आए। अब फ्रांस के साथ विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी से भारत के व्यापार, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में सशक्तीकरण की संभावनाओं को और बल मिलेगा। भारत और फ्रांस ने परस्पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष समझौता किया है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों और कंपनियों को अब दोहरा कर नहीं देना पड़ेगा। इससे द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आवागमन को नई गति मिलेगी।

गौरतलब है कि फ्रांस की मदद से कर्नाटक के वेमागल में एयरबस एच-125 हेलिकाप्टरों के निर्माण के लिए कलपुर्जों को जोड़ने का कारखाना भी स्थापित किया गया है, जहां अब काम शुरू हो गया है। यहां दुनिया के ऐसे शक्तिशाली हेलिकाप्टर का निर्माण किया जाएगा, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा।

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच 'हैमर' मिसाइलों के उत्पादन को लेकर भी अहम समझौता हुआ है। इसके तहत भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सैफरान संयुक्त उद्यम स्थापित करेगी। यह सच है कि फ्रांस, भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और अब दोनों देशों के बीच सहयोग का नया अध्याय शुरू हो रहा है।

विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पहल फ्रांस की विशेषज्ञता और भारत की विशाल क्षमता को एक साथ लाने का प्रयास है और इससे निश्चित तौर पर भारत की विनिर्माण एवं निर्यात क्षमताओं में इजाफा होगा।

भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। फ्रांसिसी राष्ट्र प्रमुख इमैनुअल मैक्रों से बातचीत और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा है कि अब ऐसे हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर भी उड़ सकेगा।

आखिर जातीय, धार्मिक व क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर कैसे पाएंगे काबू?

दुनिया को 'वसुधैव कुटुम्बकम' का संदेश देने वाला जनतांत्रिक भारत आज जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली 'ब्रितानी' व 'मुगलिया' सियासत के चक्रब्यूह में फंसा पड़ा है। इससे 'सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया' जैसी उसकी उदात्त सोच भी कठघरे में खड़ी प्रतीत हो रही है। यहां की प्रतिभाशाली और प्रभुत्ववाली सामान्य जातियों (सवर्णों) के खिलाफ देश में जो लक्षित पूर्वाग्रही राजनीति कथित दलित-ओबीसी नेताओं के द्वारा की जा रही है, उससे देश व समाज के सामने विभिन्न नैतिक व वैधानिक सवाल उठ खड़े हुए हैं!

हैरत की बात है कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के नारे लगाए जाते हैं। कहीं जाति, कहीं धर्म और कहीं भाषा-क्षेत्र के नाम पर लोगों के उत्पीड़न हो रहे हैं। वहीं कहीं सामाजिक न्याय आधारित आरक्षण और साम्प्रदायिक सोच आधारित अल्पसंख्यकवाद के अव्यवहारिक पहलुओं को हवा देकर आमलोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। आलम यह है कि ऐसे करने वाले नेता, उनके हमकदम मस्त हैं, जबकि आमलोग त्रस्त हैं।

हद तो यह कि हमारे संविधान के संरक्षक अनर्गल दलीलें देकर मानवता की गला घोंट रहे हैं, जबकि यही प्रवृत्ति कतिपय संविधान निर्माताओं में भी दिखी थी। वहीं आज के कथित रखवाले जन्मांध 'धृतराष्ट्र' की भूमिका निभा रहे हैं।इनके जैसे ही नेताओं की खामोशी से जहां 1947 में साम्प्रदायिक विभाजन हुआ, वहीं इनके षडयंत्र से आजादी के बाद से ही जातीय, क्षेत्रीय व नवसंप्रदायिक विभाजन की प्रवृत्ति हावी होती दिख रही है, जो आज भी जारी है। ऐसे में एक और महाभारत छिड़ना तय है। पुनः विभाजन होना तय है। इतिहास

साक्षी है कि जब कभी भी महाभारत होता है तो संख्याबल पर बुद्धिबल ही भारी पड़ती है और आगे भी यही होगा।

कहना न होगा कि कोई भी लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता व बन्धुत्व की बुनियाद पर मजबूत होता है, लेकिन जब बहुमत की सियासी शरारत शुरू हो जाए और वामपंथियों के वर्गवादी राजनीति को मात देने के लिए पूंजीवादी प्रभाव वश जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की सियासत तेज हो जाए तो देर सबेर राष्ट्र राज्य का बिखरना तय होता है। इसलिए इनसे जुड़े राजनीतिक हथकंडों और उन्हें शह देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को यदि समय रहते ही नहीं बदला गया तो बाद में इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होगा!

ऐसा इसलिए कि जातिवादी कैंसर, सांप्रदायिक एड्स और क्षेत्रवादी तपेदिक (टीबी) से शांतिप्रिय व सहनशील भारतीय समाज सदियों से ग्रसित है, लेकिन बीती सदी में इन्हें एक कानूनी स्वरूप देकर स्थिति को जटिल चुनौती बना दी गई है। किसी समूह के इतिहास को साक्षी मानकर उनके वर्तमान को रौंदने की जो सियासी प्रवृत्ति भारत में हावी है, उससे सामान्य व कथित सवर्ण जातियों में भारी रोष व्याप्त है।

इसलिए समावेशी संवैधानिक प्रावधानों, हिंसा-प्रतिहिंसा पर समान कानूनी सख्ती और सामाजिक जागरूकता के संयोजन से ही अब इस जटिल स्थिति से निबटना संभव है, लेकिन हमारी सियासी सोच इसके विपरीत है। वह आज भी विदेशी फूट डालो, शासन करो पर केंद्रित है। लिहाजा, कतिपय कानूनी उपाय अपेक्षित हैं। पहले चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों और नेताओं के भाषणों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए, तथा की धारा 153ए (समूहों के बीच शत्रुता फैलाना), 295ए (धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाना) और प्रतिनिधित्व ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123(3) के तहत तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाकर, जैसे नफरत भरी भाषा पर त्वरित गिरफ्तारी और पार्टी मान्यता रद्द करने का प्रावधान जोड़ना, ऐसे हथकंडों पर अंकुश लग सकता है।

लगे हाथ संस्थागत सुधार के लिए भी समवेत कदम उठाने होंगे। खासकर राजनीतिक दलों को टिकट वितरण और मंत्रिमंडल गठन में जाति-धर्म आधारित समीकरणों से ऊपर उठना होगा, जबकि चुनाव सुधारों के जरिए आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने वाले एआई-जनरेटेड कंटेंट और प्रचार पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए, जैसा कि हालिया चुनावी दौर में देखा गया।

वहीं, सामाजिक व शैक्षिक प्रयास से भी इस स्थिति से निबटा जा सकता है। विशेष कर शिक्षा प्रणाली में समावेशी पाठ्यक्रम लागू कर नई पीढ़ी को जाति-धर्म से ऊपर उठने की प्रेरणा दी जाए, तथा धर्मगुरुओं और सामाजिक नेताओं पर निगरानी रखी जाए। मतदाताओं को जागरूक अभियान चलाकर वोटिंग में योग्यता और नीतियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि विभाजनकारी रणनीतियां अप्रभावी हो जाएं।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी दो टूक शब्दों में कहा है कि राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि गाइडलाइन बनने पर भी उनका पालन कौन करेगा, क्योंकि भाषण विचारों से उत्पन्न होते हैं और इन्हें नियंत्रित करना कठिन है। कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, साथ ही राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर भी इशारा किया।

जस्टिस बागची ने कहा कि हेट स्पीच पर पहले से सिद्धांत बने हैं, लेकिन आदेश लागू करना चुनौतीपूर्ण है। कोर्ट ने जहरीले सामाजिक माहौल की चिंता स्वीकारी, लेकिन चुनिंदा नेताओं को टारगेट करने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की नसीहत दी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के भाषणों को हेट स्पीच से रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने की मांग की थी।

याचिका में दो प्रमुख दिशानिर्देश मांगे गए थे। पहला, संवैधानिक पदों या सार्वजनिक कार्यालयों पर बैठे लोगों के भाषण संवैधानिक नैतिकता के अधीन हों और दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। दूसरा, इन पदधारकों के सार्वजनिक भाषणों को नियंत्रित करने के लिए बिना पूर्व सेंसरशिप के दिशानिर्देश जारी किए जाएं, ताकि संवैधानिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित हो।

उल्लेखनीय है कि यह जनहित याचिका 12 पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों और सिविल सोसायटी सदस्यों द्वारा दायर की गई थी। इसमें असम सीएम हिमंत बिस्व सरमा, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के कथित नफरती बयानों का हवाला दिया गया। हालांकि कोर्ट ने इसे पक्षपाती मानते हुए नई व्यापक याचिका दायर करने को कहा। जिसमें अन्य नेताओं की टिप्पणियों का भी उल्लेख हो।

बता दें कि गत 16 फरवरी 2026 को चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने रूप रेखा वर्मा समेत 12 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार किया। जिसमें नेताओं और मीडिया के लिए हेट स्पीच व भाषणों पर दिशानिर्देश बनाने की मांग थी, खासकर असम सीएम हिमंत बिस्व सरमा के कथित बयानों के संदर्भ में। लेकिन कोर्ट ने मौजूदा याचिका पर सुनवाई से इनकार कर नई याचिका दायर करने को कहा।

शोक का शिष्टाचार, क्या सोशल मीडिया ने दुख की भाषा बदल दी है

सार्वजनिक शोक कई बार रणनीतिक माना जाता है- सहानुभूति, या सांस्कृतिक निकटता का निमंत्रण। कुछ लोग शोक सामग्री की इस नई लहर को 'प्रदर्शनकारी शोक' कहते हैं, क्योंकि ये 'लाइक' की गिनती संभावित रूप से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने या कुछ मामलों में पैसे भी दिला सकती है। जब 26 जनवरी, 2020 को अमेरिका के मशहूर बास्केटबाल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की मृत्यु हुई, तो सोशल मीडिया मानो एक विशाल स्मारक बन गया, लेकिन शोक मनाने वालों की आलोचना हुई। कहा गया कि आप एक ऐसे बास्केटबाल खिलाड़ी के बारे में आनलाइन क्यों आंसू बहा रहे हैं, जिसे आप निजी तौर पर जानते तक नहीं! मगर जो लोग सचमुच दुख का इजहार करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आनलाइन माहौल अक्सर भ्रामक बन जाता है।

सच्चे दुख को कई बार संदेह, आलोचना या इस धारणा से देखा जाता है कि यह सब दिखावा है। सोशल मीडिया तुलना और प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकती है, जो आनलाइन शोक तक भी फैल जाती है। कौन ज्यादा बेहतर शोक मना रहा है, किसने सबसे अच्छा श्रद्धांजलि संदेश लिखा, किसने सबसे अच्छी तस्वीर पोस्ट की, कौन सबसे ज्यादा करीब था..! आनलाइन शोक के सामाजिक पदानुक्रम को समझना थोड़ा मुश्किल है। बहुत जल्दी या बहुत बार पोस्ट करने से यह आभास हो सकता है कि कोई व्यक्ति मृतक के उतने करीब नहीं था, जितना दूसरे सोचते हैं।

निजी तौर पर दोस्तों के बीच संवेदनशील बातचीत होती थी, जहां दुख वास्तविक लगता था। मगर आनलाइन की दुनिया में सब कुछ बदल गया है। सोशल मीडिया के मंचों पर शोक बनावटी महसूस होता है। यह वास्तविक दुख से ज्यादा धारणा प्रबंधन जैसा लगता है। पश्चिमी संस्कृति में खुले तौर पर दुख व्यक्त करना अक्सर नापसंद किया जाता है, लेकिन अन्य संस्कृतियों में दुख सामुदायिक होता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से शोक मनाना यह दर्शाता है कि व्यक्ति उस समुदाय का हिस्सा है। जैसे-जैसे युवा पीढ़ी शयनकक्ष और निजी बातचीत से सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर दुख को स्थानांतरित कर रही है, मृत्यु या किसी बुरी घटना के बारे में बातचीत सार्वजनिक चौराहे पर लौट रही है। कुछ मायनों में, अगर हम अपने दुख के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, तो यह ऐसा है- क्या आपको परवाह भी थी?

संचार के डिजिटल तरीकों की अवैयक्तिक प्रकृति ने जताई जा रही सहानुभूति की गहराई और ईमानदारी को लेकर भी चिंताएं पैदा की हैं। भौतिक मौजूदगी की कमी और गलत संचार या संवाद की संभावना से व्यक्ति तब अलग-थलग या बेसहारा महसूस कर सकता है, जब उसे सबसे ज्यादा दया और समझ की जरूरत होती है। दुख और सहानुभूति जताने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे अभी तक ज्यादा पारंपरिक तरीकों की पूरी तरह से जगह नहीं माना जाता है।

पिछले एक दशक में सोशल मीडिया ने मृत्यु और शोक से जुड़ी पारंपरिक वर्जनाओं को चुनौती दी है, जिससे निजी अनुष्ठान सार्वजनिक, सुलभ दुख की अभिव्यक्तियों में बदल गए हैं। हालांकि डिजिटल शोक निजी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से साझा करने से शोक मानदंडों पर खरा उतर रहा है या नहीं, यह बहस का विषय बन चुका है।

ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने शोक की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण कर दिया है, जिससे कोई भी किसी खास व्यक्ति की मौत के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक तरह का भाव-विरेचन या विरोध है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सांस्कृतिक गिरावट का एक संकेत मानते हैं। मौत का जश्न मनाना (यहां तक कि एक अनैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की मौत का भी) मृतक और ऐसे उल्लास में भाग लेने वालों दोनों को अमानवीय बनाने का जोखिम लिए होता है। शोक संदेशों में तथ्यों को सम्मान के संतुलित लहजे के साथ मिलाया जाता रहा है। यहां तक कि जब मृतक बहुत नेक नहीं था, तब भी शोक संदेश लिखने वाले अक्सर इस कहावत का पालन करते थे कि मृतक के बारे में कुछ भी बुरा न कहें। मृतक के बारे में अच्छा ही कहें। मौत खुद एक निश्चित विनम्रता की मांग करती है। ऐसे मृत लोग (खासकर प्रसिद्ध या शक्तिशाली) प्रतीक बन जाते हैं- शक्ति, असफलता, आशा या पाखंड केष्ठ। उनका निधन न केवल यह परिभाषित करने का अवसर बन जाता है कि वे कौन थे, बल्कि यह भी कि समाज उनकी याद में किस चीज को महत्त्व देना या बुरा कहना चुनता है। सोशल मीडिया ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति पर चलता है। शोक संदेश जीवन के योगदानों का लेखा-जोखा रखने या कम से कम गरिमा के साथ उसके अंत को स्वीकार करने का होता है, हिसाब बराबर करने का जरिया नहीं। मृतक के कार्यों की परवाह किए बिना गंभीरता और सम्मान की उम्मीद आज के शोर मचाते मीडिया वाले माहौल में बेतुकी है, जहां हर मौत सुर्खियों में आई चर्चा का एक अवसर है। हमें सुविधा और करुणा के बीच की पतली रेखा को समझना होगा। जब कोई, जिसकी हम परवाह करते हैं, किसी मुश्किल समय से गुजर रहा होता है, जैसे किसी प्रियजन को खोना, तो यह स्वाभाविक है कि हम अपना समर्थन और संवेदनाएं देना चाहें। फिर भी मानवीय स्वभाव है कि हम ऐसी स्थितियों से दूर रहें, जो मुश्किल या असहज लगती हैं- खासकर जब हमें यकीन न हो कि क्या कहना है।

सौर ऊर्जा की चमक में कटते पेड़, क्या पर्यावरण पर भारी पड़ रही है हरित क्रांति

पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में राज्य वृक्ष 'खेजड़ी' को काटे जाने और गांवों की चरागाह भूमि के अधिग्रहण का व्यापक स्तर पर विरोध होना कोई सामान्य घटना नहीं है। स्थानीय लोगों की ओर से इन दरख्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पारंपरिक चरागाहों के संरक्षण की मांग ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस सौर ऊर्जा को पर्यावरण हितैषी माना जाता है, क्या उसी के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना उचित है?

वैसे देखा जाए तो भारत पिछले एक दशक में जिस तेज गति से सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर हुआ है, वह न केवल तकनीकी प्रगति का प्रमाण है, बल्कि वैश्विक जलवायु संकट के प्रति देश की रणनीतिक समझ का भी संकेत देता है। वर्ष 2014 में जहां भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता मात्र तीन गीगावाट के आसपास थी, वहीं आज यह 135 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। यह वृद्धि केवल संख्यात्मक नहीं है; यह उस राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति समर्थन और पूंजी निवेश का परिणाम है, जिसने सौर ऊर्जा को भारत की ऊर्जा नीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, कार्बन डाइआक्साइड और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाना तथा ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना- ये सभी लक्ष्य सौर ऊर्जा के विस्तार से जुड़े हैं।

सौर ऊर्जा की मूल अवधारणा अत्यंत सरल और नैतिक रूप से आकर्षक है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा न तो प्रदूषण फैलाती है, न ही सीमित संसाधनों पर किसी तरह का दबाव डालती है। कोयला, तेल और गैस आधारित विद्युत उत्पादन के विपरीत, सौर ऊर्जा उत्पादन के दौरान न तो धुआं निकलता है, न राख बनती है और न ही कार्बन डाइआक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड या नाइट्रोजन आक्साइड जैसी घातक गैसों का उत्सर्जन होता है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा को 'स्वच्छ', 'हरित' और 'नवीकरणीय' कहा गया है, और इसी आधार पर इसे वैश्विक जलवायु समाधान का प्रमुख साधन माना गया है।

मगर नीति-निर्माण में कोई भी समाधान तब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक उसके सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का सम्यक आकलन न किया जाए। भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में तेजी के साथ-साथ अब एक गंभीर प्रश्न भी उभर कर सामने आ रहा है कि क्या सौर ऊर्जा का मौजूदा विकास माडल वास्तव में पर्यावरणीय दृष्टि से उतना ही लाभकारी है, जितना कि उसे माना जा रहा है? विशेषकर तब, जब सौर परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और हरे-भरे पेड़ों को काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

राजस्थान इस मामले में एक उदाहरण है। देश का यह राज्य सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं से परिपूर्ण है; वर्ष में 300 से अधिक धूप वाले दिन, विशाल भूभाग और अपेक्षाकृत कम जनसंख्या घनत्व। यही कारण है कि राजस्थान आज भारत के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है। मगर यही प्रदेश पिछले कुछ अरसे में बहुमूल्य वृक्षों की कटाई को लेकर सामाजिक और पर्यावरणीय असंतोष का केंद्र भी बन गया है। यहां सौर परियोजनाओं के लिए जिन क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है, वे केवल खाली भूमि नहीं है; वे जीवित पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनमें वृक्ष, पशु-पक्षी और स्थानीय समुदायों का जीवन गहराई से जुड़ा हुआ है।

नीतिगत स्तर पर अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि सौर संयंत्रों के लिए 'बंजर' भूमि का उपयोग किया जा रहा है। मगर पर्यावरण विज्ञान बताता है कि बंजर दिखाई देने वाली भूमि भी पारिस्थितिकी की दृष्टि से निष्क्रिय नहीं होती। विशेषकर शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान में 'खेजड़ी' जैसे वृक्ष पर्यावरण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वृक्ष न केवल कार्बन डाइआक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि मिट्टी को बांधते हैं, जल संरक्षण में सहायता करते हैं और स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं। सामान्यतः एक मेगावाट सौर संयंत्र के लिए लगभग चार से पांच एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। यदि उस भूमि पर दर्जनों या सैकड़ों वृक्ष मौजूद हैं, तो उनके कटने से कार्बन सोखने की जो क्षमता समाप्त होती है, उसकी भरपाई सौर पैनल द्वारा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा से तुरंत नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सौर ऊर्जा से जो कार्बन उत्सर्जन बचाया जाता है, उसका एक हिस्सा पेड़ों की कटाई के कारण खो भी जाता है।

अगले कुछ दशकों में जब आज लगाए जा रहे सौर पैनल बड़ी मात्रा में अनुपयोगी होंगे, तब उनके निस्तारण से उत्पन्न ई-कचरा और उससे जुड़े पर्यावरणीय जोखिम एक नई चुनौती बनकर सामने आएंगे। यदि इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि सौर ऊर्जा का वर्तमान मूल्यांकन अधूरा है; यह लागत और उत्पादन पर केंद्रित है, पर शुद्ध पर्यावरणीय लाभ की गणना से दूर है।

ऐसे में सौर ऊर्जा के मूल्यांकन को केवल लागत-प्रति-यूनिट या स्थापित क्षमता के आधार पर नहीं देखा जा सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक सौर परियोजना का जीवन-चक्र आधारित पर्यावरणीय आकलन किया जाए। इसमें यह देखा जाना चाहिए कि परियोजना के निर्माण, भूमि परिवर्तन, वृक्ष कटाई, संचालन और अंततः सौर पैनलों के निस्तारण तक कुल कितनी पर्यावरणीय लागत उत्पन्न होती है, और उसके मुकाबले वास्तविक पर्यावरणीय लाभ कितना है। जब तक यह संतुलन स्पष्ट नहीं होगा, तब तक 'स्वच्छ ऊर्जा' का दावा अधूरा रहेगा।

वर्तमान व्यवस्था में सौर परियोजनाओं को तेजी से स्वीकृति देने की होड़ में पर्यावरणीय मूल्यांकन को औपचारिकता मात्र बना दिया गया है। पेड़ों की कटाई के बदले प्रतिपूरक वृक्षारोपण की शर्तें तो लगाई जाती हैं, मगर यह शायद ही कभी देखा जाता है कि लगाए गए पौधे जीवित रहते हैं या नहीं, और क्या वे उसी पारिस्थितिक क्षेत्र में लगाए गए हैं, जहां नुकसान हुआ है।

एक परिपक्व वृक्ष और एक नवरोपित पौधे के बीच के पर्यावरणीय अंतर को नीति में शायद ही कभी गंभीरता से लिया जाता है। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या सौर ऊर्जा का वर्तमान विस्तार माडल वास्तव में जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक है, या वह अनजाने में एक नई पर्यावरणीय समस्या को जन्म दे रहा है।

यदि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में हम कार्बन सोखने के प्राकृतिक तंत्र को ही नष्ट करना शुरू दें, तो यह एक प्रकार का नीतिगत विरोधाभास होगा। स्वच्छ ऊर्जा का उद्देश्य केवल चिमनियों से निकलने वाले धुएं को रोकना नहीं है, बल्कि पृथ्वी की प्राकृतिक संतुलन प्रणालियों को सुदृढ़ करना भी है। मगर इस समस्या का समाधान सौर ऊर्जा को सीमित करना नहीं है, बल्कि उसके विकास के तरीके को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। नीति-निर्माताओं को यह स्वीकार करना होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन अनिवार्य है।

इमारतों की छतों, नहरों और परित्यक्त औद्योगिक भूमि पर सोलर पैनल लगाना तथा रेलवे और राजमार्ग गलियारा जैसे विकल्प भूमि एवं वृक्षों की कटाई पर दबाव कम कर सकते हैं। साथ ही 'एग्रीवोल्टाइक' जैसी प्रणालियां भूमि के द्वि-उपयोग का मार्ग खोलती हैं, जहां कृषि और सौर ऊर्जा का उत्पादन साथ-साथ हो सकता है।

भारत की सौर नीति को अब एक नए चरण में प्रवेश करना होगा, जहां लक्ष्य केवल गीगावाट जोड़ना नहीं, बल्कि वास्तविक पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित करना हो। सौर ऊर्जा तभी नवीकरणीय कही जा सकेगी, जब उसका विस्तार वृक्षों, भूमि और स्थानीय पारिस्थितिकी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए हो। अन्यथा, स्वच्छ ऊर्जा का यह सपना अपनी ही जड़ों को काटता हुआ आगे बढ़ेगा।

आज मानव सभ्यता विकास के चरम पर है। भौतिक और तकनीकी प्रगति ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है। मगर भौतिक और तकनीकी प्रगति की इस आपसी प्रतिस्पर्धा ने मानव जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। जबकि मानव के लिए यह पृथ्वी ही सबसे सुरक्षित ठिकाना है। विज्ञान आज तक इसका दूसरा विकल्प नहीं खोज पाया है।

जल जीवन मिशन परियोजना का सीडीओ ने किया औचक निरीक्षण

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने विकास खंड डीघ की ग्राम पंचायत खेदोपुर में शुक्रवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पेयजल परियोजना का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मौके पर निर्माण कार्य बंद पाया गया। स्थल पर बाउंड्री वॉल, गेट एवं पंप हाउस का निर्माण तो पूर्ण मिला, लेकिन कार्यस्थल पर परियोजना संबंधी सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया था।

मुख्य विकास अधिकारी ने अधिशासी अभियंता, जल निगम को निर्देशित किया कि परियोजना की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें तथा कार्य शीघ्र प्रारंभ कराते हुए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

खादी विभाग ने देवाजितपुर में लगाया जागरूकता शिविर

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिला खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय द्वारा विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत विकास खंड ज्ञानपुर के देवाजितपुर गांव में शुक्रवार को एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया।

जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने शिविर की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शनी, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना एवं माटीकला टूल्स किट वितरण योजना सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि विभाग रोजगार सृजन कर समृद्धि की नई राह बुन रहा है।

जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार ने युवाओं व महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कौशल विकास, स्टार्टअप स्थापना और आसान ऋण सुविधा के माध्यम से हर हुनरमंद हाथ को काम देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खादी विभाग गांव-गांव चौपाल लगाकर अंत्योदय वर्ग को लाभान्वित कर रहा है।

प्रशिक्षण समन्वयक आरसेटी देवेन्द्र दुबे, उद्योग अधिकारी विवेक सिंह तथा जिला मिशन प्रबंधक एनआरएलएम अज़म ने भी विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। आरसेटी प्रशिक्षण केंद्र में ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, रेफ्रिजरेटर-एसी मरम्मत, अगरबत्ती, अचार, पापड़, डिटर्जेंट आदि ट्रेड में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के बाद खादी विभाग के माध्यम से ऋण एवं अनुदान की सहायता से स्वरोजगार स्थापित करने की बात कही गई।

कार्यक्रम का संचालन ग्रामोद्योग अधिकारी राजेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ सहायक पवन कुमार ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा माटीकला योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम प्रधान देवाजितपुर कृष्ण कांत उपाध्याय, इद्रेश दुबे, समहू सखी रेशमा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

उद्यमियों के लिए पूंजी की रुकावट नहीं होगी : सीडीओ

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मार्गदर्शन में यूनियन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के निर्देशानुसार जनपद में वृहद ऋण वितरण शिविर एवं वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने कहा कि युवाओं को उद्यम स्थापना के लिए पूंजी की समस्या नहीं आने दी जाएगी और बैंक प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने लाभार्थियों से ऋण का सदुपयोग एवं समय पर पुनर्भुगतान की अपील की। इस दौरान लगभग 65 लाभार्थियों को करीब 4 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि शिविर से जिले में ऋण प्रवाह को गति मिलेगी और सीडी अनुपात मजबूत होगा। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए गए, जहां कृषकों, महिला समूहों और युवा उद्यमियों ने जानकारी प्राप्त की। साइबर धोखाधड़ी से बचाव पर भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत ज्ञानपुर के चेयरमैन घनश्यामदास गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

2030 तक भदोही को सशक्त एवं सामर्थ जनपद बनाने हेतु व्यापक विचार-विमर्श, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

'सशक्त जनपद-समृद्ध उत्तर प्रदेश' का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हर भदोहीवासी इसमें भागीदारी निभाएं - जिलाधिकारी

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कम वाले 20 जनपदों में शामिल जनपद भदोही को वर्ष 2030 तक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं सामर्थ जनपद बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के संभ्रांत नागरिकों, समाजसेवियों, विशेषज्ञों एवं अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर सुझाव प्राप्त किए गए।

बैठक में जिलाधिकारी के नेतृत्व में कृषि, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन एवं महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार एवं विकास की संभावनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में प्राथमिक क्षेत्र कृषि को लाभकारी बनाने हेतु पारंपरिक खेती से हटकर सब्जी, फल, फूल एवं औषधीय खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। साथ ही किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से सामूहिक खेती एवं विपणन को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन एवं मछली पालन जैसे सहायक व्यवसायों को आय के प्रमुख स्रोत के रूप में विकसित करने पर विशेष चर्चा की गई।

जनपद की पहचान बुनकर उद्योग के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय उद्योगों को सशक्त करने पर बल दिया गया। युवाओं को स्टार्टअप, सूक्ष्म उद्यम, हस्तशिल्प एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया गया। घर आधारित उद्योगों जैसे बुनाई, कढ़ाई, अगरबत्ती एवं पापड़ निर्माण को बढ़ावा देने तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आय सृजन से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।

युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं डिजिटल स्किल सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने पर सहमति बनी।

जनपद में स्थित सीतामढ़ी जैसे धार्मिक स्थलों को विकसित कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। इसके अंतर्गत होम-स्टे, टूरिस्ट गाइड एवं स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित करने पर विचार व्यक्त किए गए।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से छोटे उद्योग स्थापित करने, प्रशिक्षण एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से परिवार की आय एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक के अंत में जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सभी उपस्थित जनों के सुझावों एवं विचारों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि जनपद के समग्र विकास के लिए सभी वर्गों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि किसान आधुनिक खेती अपनाएं, युवा कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन करें, महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ें और सभी नागरिक स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करें, तो वर्ष 2030 तक जनपद भदोही को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 'सशक्त जनपद - समृद्ध उत्तर प्रदेश' का लक्ष्य तभी साकार होगा जब प्रत्येक नागरिक इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत अनिरुद्ध त्रिपाठी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संतोष कुमार चक, उपायुक्त जी राम जी राजाराम, डीडीओ ज्ञान प्रकाश, जिला सूचना अधिकारी डॉ पंकज कुमार, विधायक औराई प्रतिनिधि विजय शंकर दुबे छेदीलाल यादव प्रतिनिधि एमएलसी, अनीता बिदं ग्रामप्रधान मवैया हरदोपटटी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी रमेश चंद्र, मुकेश कुमार ईएसएमसहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य नागरिकों जनपद को 2030 तक विकसित बनाने के लिए अपने अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किया।

ग्राम पंचायत शेरवा में स्वच्छता मार्ट का बीडीओ ने किया उद्घाटन

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देश पर विकास खंड भदोही की ग्राम पंचायत शेरवा में गुरुवार को स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में जिलाधिकारी के महत्वपूर्ण पहल के तहत स्वच्छता मार्ट का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता मार्ट के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता संबंधी सामग्री जैसे कूड़ेदान, सफाई उपकरण, फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर आदि उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे गांव में साफ-सफाई की व्यवस्था मजबूत होगी तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मनोज कुमार मौर्य ने ग्रामवासियों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी से सफल होने वाली सतत प्रक्रिया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान जावित्री देवी, पंचायत सहायक ज्योति मौर्या, रोजगार सेवक विजय कुमार, चंद्रेश कुमार मौर्य तथा केयर टेकर कुसुम देवी सहित अन्य ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने स्वच्छता मार्ट की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे गांव के लिए उपयोगी पहल बताया।

दुर्गागंज थाना प्रभारी निरीक्षक ने की पीस कमेटी की बैठक

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। दुर्गागंज थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार गुप्ता ने आगामी त्यौहार होली एवं रमजान को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक की। इस दौरान दोनों धर्मों के लोगों से बातचीत किया और कहां की कोई समस्या हो तो आप लोग बताए आप लोगों की समस्या का हल किया जाएगा साथ ही होली में किसी भी प्रकार की अश्लीलता करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एस आई रामलाल रॉय सोनू पांडेय कमलेश फिरोज अहमद, आदि मौजूद रहे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति की बैठक सम्पन्न

जाति , धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर आपस में प्रेम सौहार्दपूर्वक आगे बढ़ना ही एकीकरण बैठक का उद्देश्य-अनिरुद्ध त्रिपाठी

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने तथा जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत अनिरुद्ध त्रिपाठी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संतोष कुमार चक, उपायुक्त जी राम जी राजाराम, डीडीओ ज्ञान प्रकाश, विधायक औराई प्रतिनिधि विजय शंकर दुबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि अध्यक्ष जिला पंचायत अनिरुद्ध त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि जाति, धर्म एवं वर्ग से ऊपर उठकर यदि देखा जाए तो सभी लोग मानव हैं, और मानव होने के नाते प्रत्येक त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाना ही एकीकरण समिति का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जनपद भदोही अपनी गंगा-जमुनी तहजीब एवं आपसी मेल-जोल के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आगे भी बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जनपद की महान विभूतियों के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे नई पीढ़ी उनके जीवन एवं योगदान से परिचित हो सके और समाज में सकारात्मक प्रेरणा प्राप्त हो। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के संबंध में उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों/डीजे का प्रयोग निर्धारित मानकों एवं समय-सीमा के अनुरूप ही किया जाए, जिससे विद्यार्थियों एवं आमजन को असुविधा न हो।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि जिला एकीकरण समिति का मुख्य उद्देश्य

विभिन्न त्यौहारों के दौरान राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में ईद एवं होली के पर्व निकट हैं, जो आपसी भाईचारे एवं खुशियां बांटने के प्रतीक हैं। सभी जनपदवासी इन पर्वों को मिल-जुलकर एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी भी क्षेत्र में त्यौहारों के पूर्व कोई समस्या या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सूचना समय रहते जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं, जिससे उसका समाधान किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि त्यौहारों के दौरान जनसुविधाओं के दृष्टिगत नगर निकायों एवं संबंधित विभागों को पेयजल, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद भदोही अपने ताना-बाना उद्योग के साथ-साथ आपसी भाईचारे के लिए भी जाना जाता है, जिसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल ने कहा कि सभी त्यौहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मैत्रीपूर्ण व भातृत्व भावना सहित सहयोग व समन्वय के विचार पर बल दिया।

बैठक में वरिष्ठ नागरिक डॉ लक्ष्मीधर चतुर्वेदी ने एकीकरण समिति की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने पर बल दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जनपद की महान विभूतियों के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे नई पीढ़ी उनके जीवन एवं योगदान से परिचित हो सके और समाज में सकारात्मक प्रेरणा प्राप्त हो।

वरिष्ठ साहित्यकार डॉ कृष्णावतार त्रिपाठी 'राही' ने कहां कि ताने-बाने का शहर जनपद भदोही, गंगा- जमुनी तहजीब का सदैव प्रवाहक रहा है। उन्होंने जनपद में राष्ट्रीय एकता , भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक भावना, सौहार्दपूर्ण वातावरण के निरंतरता पर बल दिया।

समाजसेवी एवं व्यापार मंडल पदाधिकारी मो0 शकील खान ने कहा कि महापुरुषों के जन्म दिवस पर सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने गुरुद्वारों में सभी लोगों द्वारा एक साथ बैठकर लंगर ग्रहण करने की परंपरा को कौमी एकता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

शिक्षक एवं पर्यावरणविद अशोक गुप्ता ने कहा कि अहिंसा एवं आपसी सद्भाव के सिद्धांतों को अपनाकर ही त्यौहारों को मनाया जाए, तभी एकीकरण समिति की बैठक का उद्देश्य सफल होगा। इस अवसर पर सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रकाशित सूचना डायरी-2026, टेबल कैलेंडर एवं 'विरासत भी विकास भी - काम दमदार डबल इंजन सरकार' थीम पर आधारित कैलेंडर जिला सूचना अधिकारी डॉ पंकज कुमार द्वारा उपस्थित जनों को वितरित किए गए।

बैठक में छेदीलाल यादव प्रतिनिधि एमएलसी, अनीता बिना ग्रामप्रधान मवैया हरदोपटटी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी रमेश चंद्र, मुकेश कुमार ईएसएम ने भी एकीकरण पर बल दिया।

क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर सीएम से मिले सांसद डॉ. विनोद बिंद

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। लोकसभा क्षेत्र भदोही के सांसद डॉ. विनोद बिंद ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात कर अपने लोकसभा क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, युवाओं के लिए रोजगार सृजन तथा क्षेत्र की प्रमुख स्थानीय समस्याओं के समाधान जैसे विषयों पर सकारात्मक संवाद हुआ। साथ ही, चल रही विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने और नई योजनाओं की स्वीकृति दिलाने पर विशेष जोर दिया गया।

मुलाकात के दौरान सांसद ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थानों की स्थापना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के माध्यम से आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना लक्ष्य है।

सांसद डॉ. विनोद बिंद ने कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवाओं के लिए स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु भी ठोस पहल की जा रही है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. राकेश दुबे, अजय पटेल, संतोष बिंद, आदित्य मौर्य सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में मधुमेह नियंत्रण पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

ज्ञानपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में शुक्रवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मधुमेह नियंत्रण विषय पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. रमेश चंद्र यादव द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया।

मुख्य वक्ता पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बॉम्बे अस्पताल के डॉ. सुशील मिश्रा ने कहा कि मधुमेह एक गंभीर रोग है, जिसमें रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो आंख, गुर्दा, हृदय और नसों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक इतिहास, असंतुलित आहार, अधिक मीठा व वसा युक्त भोजन, शारीरिक श्रम की कमी तथा अधिक वजन इसके प्रमुख कारण हैं।

उन्होंने बताया कि अधिक प्यास लगना, बार-बार मूत्र आना, शरीर का वजन कम होना, थकान तथा दृष्टि कमजोर होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग, चिकित्सकीय परामर्श, औषधि सेवन एवं आवश्यकता पड़ने पर इंसुलिन उपचार से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है।

कार्यक्रम में डॉ. ईरा त्रिपाठी, डॉ. मधु विश्वकर्मा, डॉ. लता सहित महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में सभी को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और मधुमेह के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।

जनपद में मेडिकल कॉलेज की मांग तेज, केंद्रीय मंत्री चिराग़ पासवान ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर भदोही में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है।

केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि हाल ही में लोजपा के उत्तर प्रदेश महासचिव एवं भदोही प्रभारी कमल तिवारी ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग की थी। उसी मांग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया है।

पत्र में कहा गया है कि कालीन उद्योग के लिए विश्वविख्यात भदोही जिले में एक भी उच्च स्तरीय अस्पताल उपलब्ध नहीं है। गंभीर दुर्घटना अथवा आपातकालीन स्थिति में मरीजों को वाराणसी या प्रयागराज ले जाना पड़ता है। कई बार समय पर उपचार न मिल पाने के कारण मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है। ऐसे में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना से न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से भदोही में राजकीय मेडिकल कॉलेज की शीघ्र स्थापना सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।

मंत्री की सक्रियता पर लोजपा पदाधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। जिलाध्यक्ष विकास दुबे, धनंजय दुबे, राहुल तिवारी, गोविंद पासवान व संतोष दुबे ने कहा कि इससे जिले की बहुप्रतीक्षित मांग को नई गति मिली है।

भिवंडी महापौर चुनाव में 'खेला', भाजपा में बगावत- कांग्रेस की रणनीति सफल

भाजपा के बागी नारायण चौधरी बने महापौर

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका के हाई-वोल्टेज महापौर चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। चुनाव में भाजपा के भीतर बगावत और क्रॉस वोटिंग के चलते सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल गए। भाजपा के बागी नगरसेवक नारायण चौधरी कांग्रेस और राकांपा (शरद) के समर्थन से महापौर चुने गए, जबकि कांग्रेस के तारिक मोमिन उपमहापौर निर्वाचित हुए। इस चुनाव को राजनीतिक गलियारों में 'चंद्रपुर पैटर्न' जैसा उलटफेर माना जा रहा है, जिसमें विरोधी दल के बागियों के सहारे सत्ता हासिल की गई। चुनाव परिणामों ने भाजपा और महायुति की रणनीति को बड़ा झटका दिया, जबकि कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल रहा।

भाजपा के साथ हुआ 'खेला'......

महापौर पद के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के बागी नगरसेवकों को साथ लेकर बाजी पलट दी। भाजपा के बागी नारायण चौधरी को कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया गया और उन्हें 48 मत प्राप्त हुए। इसमें कांग्रेस के 30, राकांपा (शरद) के 12 तथा भाजपा के 6 बागी नगरसेवकों का समर्थन शामिल था। इस तरह भाजपा का नगरसेवक ही कांग्रेस के समर्थन से महापौर चुना गया। वहीं कांग्रेस के तारिक मोमिन 43 मतों के साथ उपमहापौर निर्वाचित हुए। सूत्रों के अनुसार भाजपा द्वारा अंतिम समय में महापौर उम्मीदवार बदलने का फैसला पार्टी पर भारी पड़ गया। इससे पार्टी दो गुटों में बंट गई और असंतुष्ट नगरसेवकों ने खुलकर बगावत कर दी।

■ कांग्रेस के समर्थन से तारिक मोमिन उपमहापौर
■ महायुति की फूट से बदले समीकरण

त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा तीसरे स्थान पर.....

महापौर चुनाव की प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी एवं ठाणे जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाल की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे शुरू हुई। आयुक्त अनमोल सागर और नगर सचिव अजय पाटील की उपस्थिति में मतदान कराया गया। महापौर पद के लिए 10 नामांकन दाखिल हुए थे, जिनमें से सात उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। अंतिम मुकाबला नारायण चौधरी, कोणार्क विकास आघाड़ी के विलास पाटील और भाजपा उम्मीदवार स्नेहा मेहुल पाटिल के बीच हुआ।

नारायण चौधरी को 48 मत मिले, जिसमें कांग्रेस के 30, शरद पवार की एनसीपी के 12 और भाजपा के 6 वोट मिले। जबकि विलास पाटील को 26 मत प्राप्त हुए। उन्हें शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के 12, समाजवादी पार्टी के 6, कोणार्क विकास आघाड़ी के 4 तथा भिवंडी विकास आघाड़ी के 3 नगरसेवकों का समर्थन मिला। भाजपा उम्मीदवार स्नेहा पाटिल को मात्र 16 मत मिले और पार्टी तीसरे स्थान पर रही। एक निर्दलीय नगरसेवक मतदान से अनुपस्थित रहा। धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद कोणार्क विकास आघाड़ी के उम्मीदवार विलास पाटील मतदान के लिए पुलिस बंदोबस्त में मनपा मुख्यालय पहुंचे थे।

उपमहापौर पद पर भी कांग्रेस की जीत.....

उपमहापौर पद के लिए सात नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें से चार उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक मोमिन को 43 मत मिले। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 30, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के 12 तथा भाजपा के एक नगरसेवक का समर्थन मिला।

भिवंडी विकास आघाड़ी के जावेद दलवी को 25 मत मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार सुहास नकाते को 21 मत प्राप्त हुए।

महायुति की फूट से बदले समीकरण.....

महापौर और उपमहापौर चुनाव में महायुति पूरी तरह बिखरी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। सूत्रों के अनुसार शिवसेना (शिंदे) ने भाजपा का साथ देने के बजाय महापौर चुनाव में कोणार्क विकास आघाड़ी और उपमहापौर चुनाव में भिवंडी विकास आघाड़ी का समर्थन किया.महायुति के पास लगभग 42 सीटें होने के बावजूद आपसी मतभेदों के कारण भाजपा और उसके सहयोगी सत्ता से दूर रह गए। भाजपा का महापौर बनाने का दावा पूरी तरह ध्वस्त हो गया।

उम्मीदवार बदलना पड़ा भारी....

भाजपा ने पहले नारायण चौधरी को महापौर उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन चुनाव से दो दिन पहले उनका नाम वापस लेकर हाल ही में पार्टी में शामिल हुई स्नेहा मेहुल पाटिल को उम्मीदवार बना दिया गया। इस फैसले से पार्टी में नाराजगी फैल गई और भाजपा दो गुटों में बंट गई। कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाते हुए नारायण चौधरी को समर्थन देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। भाजपा के छह नगरसेवकों की क्रॉस वोटिंग से चौधरी महापौर निर्वाचित हो गए।

भाजपा के बागी नगरसेवक.....

भाजपा से बगावत कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाले नगरसेवकों में सुहास नकाते (प्रभाग 18-डी), नंदिनी महेंद्र गायकवाड़ (17-ए), दीपा माढवी (18-बी), साबुसाद अशफाक शेख (18-सी), अश्वनी फूटाणकर (18-ए) और नारायण चौधरी (23-सी) शामिल बताए जा रहे हैं।

बताया जाता है कि इनमें से अधिकांश नगरसेवक स्थानीय भाजपा नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं और तीन नगरसेवक निर्विरोध चुने गए थे।

महापौर और उपमहापौर चुनाव के दौरान महानगरपालिका मुख्यालय पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। चुनाव परिणामों के बाद विजयी महापौर और उपमहापौर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस चुनाव परिणाम को भिवंडी की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है, जहां जोड़तोड़ की राजनीति में पहली बार कांग्रेस ने भाजपा को उसी की शैली में मात देकर मनपा की सत्ता पर कब्जा जमा लिया।

भिवंडी में रमजान के दौरान स्वच्छता बनाए रखने की अपील

नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका के घनकचरा व्यवस्थापन विभाग ने रमजान ईद के अवसर पर शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नागरिकों और व्यापारियों से विशेष सहयोग की अपील की है। महानगरपालिका क्षेत्र में 18 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 तक रमजान का पर्व मनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने स्वच्छता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मनपा प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय सहित सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि त्योहार को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में मनाने के लिए सभी को अपने-अपने क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखना आवश्यक है। जारी निर्देशों के अनुसार प्रभाग समिति क्रमांक 1 से 5 के अंतर्गत बाजार क्षेत्रों में सभी हाथगाड़ी विक्रेताओं और व्यापारियों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग डस्टबिन में रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही कचरा केवल महानगरपालिका की घंटागाड़ी या निर्धारित स्थानों पर ही डालने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना, कचरा जलाना या खुले स्थानों पर गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। प्लास्टिक थैलियों और प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग से बचने की भी अपील की गई है। पशु अवशेषों को महानगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही जमा करना होगा। हाथगाड़ी विक्रेताओं को सार्वजनिक स्थानों पर ज्वलनशील गैस का उपयोग करने से पहले स्थानीय प्रभाग कार्यालय या अग्निशमन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ घनकचरा प्रबंधन नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मनपा प्रशासन ने नागरिकों से नमाज स्थलों, बाजारों और सड़क क्षेत्रों को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही लोगों से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने और स्वच्छ शहर अभियान में भागीदारी करने का आग्रह किया गया है।

'मनसुख-पर्यटन' पर निकले मुख्यमंत्री योगी? अखिलेश यादव ने जापान दौरे को लेकर कसा तंज

लखनऊ **(एजेंसी)**। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को अपनी आगामी जापान यात्रा में क्योटो जरूर जाना चाहिए और समझना चाहिए कि सरकार वाराणसी का विकास उसी तर्ज पर क्यों नहीं कर पाई।ˆ पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप जापान जा रहे हैं, तो क्योटो जरूर जाएं, ताकि आप समझ सकें कि प्रधान-संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया, या इसकी विरासत कैसे धूमिल हुई। विरासत संरक्षण और शहरों के विकास के सकारात्मक सबक लेकर जापान से लौटें।

आगे कटाक्ष करते हुए यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी साल में मनसुख-पर्यटन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैर, अब उनके कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में, उनके आखिरी साल में–कौन कह सकता है कि हम जापान का ठीक से अध्ययन भी कर पाएंगे, किसी ठोस योजना को तैयार करना तो दूर की बात है। यह मुख्यमंत्री का 'मनसुख-पर्यटन' है–अगर वे इसे स्वीकार करते हैं, तो कम से कम लोग उन्हें जाने से पहले एक सच बोलने के लिए याद रखेंगे। क्या वे सिर्फ 'वनस्पति के विशेष अध्ययन' का निजी लाभ उठाएंगे, या इसे अपने करीबियों के साथ भी साझा करेंगे?

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अगस्त-सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान वाराणसी और क्योटो के बीच एक पार्टनर सिटी संबद्धता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में संस्कृति, कला, शिक्षा, विरासत संरक्षण और शहर के आधुनिकीकरण को सहयोग के संभावित क्षेत्रों के रूप में संदर्भित किया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में, अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है और कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे को उठाने के लिए चुनाव आयोग से समय मांगा है।

स्थानीय राजनीति में 25 साल का सफर

दूध बेचने से महापौर तक: कौन हैं नारायण चौधरी जिनकी बगावत ने बदल दिए भिवंडी के समीकरण

भाजपा से बगावत कर सेकुलर गठबंधन के समर्थन से बने महापौर

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका के 20. फरवरी शुक्रवार को हुए महापौर चुनाव में सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे नारायण रतन चौधरी अब शहर के प्रथम नागरिक बन गए हैं। भाजपा से बगावत कर सेकुलर गठबंधन के समर्थन से महापौर बनने वाले चौधरी की जीत ने न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चर्चा छेड़ दी है। उनकी राजनीतिक चाल की तुलना कई लोग एकनाथ शिंदे की बगावत से कर रहे हैं, जिन्होंने 2022 में उद्धव ठाकरे से अलग होकर सत्ता का समीकरण बदल दिया था।

महापौर चुनाव में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार बदले जाने के बाद नारायण चौधरी ने पार्टी से बगावत कर दी और कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के समर्थन से चुनाव मैदान में उतर गए। उन्हें कुल 48 मत मिले और वे स्पष्ट बहुमत के साथ महापौर निर्वाचित हुए। इस जीत ने भाजपा को बड़ा झटका दिया और शहर की राजनीति में नया समीकरण स्थापित हो गया।

दूध बेचने से शुरू हुआ सफर.......

करीब 25 वर्षों से सक्रिय नारायण चौधरी की राजनीतिक यात्रा काफी संघर्षपूर्ण रही है। भिवंडी के तडाली क्षेत्र के निवासी चौधरी ने अपने जीवन की शुरुआत दूध के व्यवसाय से की थी। बाद में उन्होंने निर्माण क्षेत्र में कदम रखा और आज वे 'नारायण डेवलपर्स' नामक निर्माण कंपनी से जुड़े बताए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर मेहनत और संगठनात्मक सक्रियता के कारण उन्होंने धीरे-धीरे अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। दूध बेचने वाले एक

साधारण कार्यकर्ता से महापौर बनने तक का उनका सफर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

2002 से शुरू हुई राजनीति.......

नारायण चौधरी ने वर्ष 2002 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और पहली बार नगरसेवक चुने गए। वर्ष 2002 से 2007 तक वे भिवंडी विकास आघाड़ी से नगरसेवक रहे। इसके बाद 2007 से 2012 के बीच उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी पकड़ मजबूत की। वर्ष 2012 में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसी दौरान 2012 से 2017 के बीच उनकी पत्नी अलका चौधरी समाजवादी पार्टी से नगरसेवक रहीं। बाद में चौधरी शिवसेना में शामिल हुए और लंबे समय तक सक्रिय रहे। बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच 2025 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इसी पार्टी के टिकट पर नगरसेवक निर्वाचित हुए।

भाजपा से बगावत बनी जीत की वजह....

इस बार पहली बार भाजपा ने उन्हें महापौर पद का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार बदलने के फैसले से चौधरी नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने बगावती रुख अपनाया और कांग्रेस नेतृत्व वाले सेकुलर गठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़ा। महापौर चुनाव में उन्हें 48 मत मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार स्नेहा पाटिल को 16 और कोणार्क विकास आघाड़ी के विलास पाटिल को 25 मत प्राप्त हुए। इस परिणाम ने भाजपा की रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया।

'किंगमेकर' की भी चर्चा......

स्थानीय राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा की भूमिका अहम रही और उन्हें इस चुनाव का 'किंगमेकर' माना जा रहा है।

नारायण चौधरी अब भिवंडी के महापौर के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर शहर का प्रथम नागरिक बनने की उनकी कहानी फिलहाल भिवंडी की राजनीति की सबसे चर्चित कहानी बन गई है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी छह जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें राजकोट - महबूबनगर स्पेशल के फेरे बढ़ाए गए

यात्रियों की सुविधा तथा होली पर्व के दौरान यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे विशेष किराए पर छह जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09075/09076 मुंबई सेंट्रल - काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09075 मुंबई सेंट्रल - काठगोदाम स्पेशल प्रत्येक बुधवार को 10:55 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन 14:30 बजे काठगोदाम पहुँचेगी। यह ट्रेन 25 फरवरी, 2026 से 25 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09076 काठगोदाम - मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 17:30 बजे काठगोदाम से प्रस्थान कर अगले दिन 21:00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन 26 फरवरी, 2026 से 26 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, हिण्डौन सिटी, भरतपुर, अछनेरा, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बदायूं, बरेली जं., बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेड़ी, किच्छा, लालकुआँ एवं हल्द्वानी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09185/09186 मुंबई सेंट्रल - कानपुर अनवरगंज साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09185 मुंबई सेंट्रल - कानपुर अनवरगंज स्पेशल प्रत्येक रविवार को 10:55 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन 15:35 बजे कानपुर अनवरगंज पहुँचेगी। यह ट्रेन 22 फरवरी, 2026 से 29 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज - मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक सोमवार को कानपुर अनवरगंज से 18:25 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 22:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फरवरी, 2026 से 30 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, मथुरा कैंट, हाथरस सिटी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज एवं बिल्हौर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09185 का सूरत स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09023/09024 बांद्रा टर्मिनस - पालिताना साप्ताहिक स्पेशल (02 फेरे)

ट्रेन संख्या 09023 बांद्रा टर्मिनस - पालिताना स्पेशल 27 फरवरी, 2026 (शुक्रवार) को 21:45 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान कर अगले दिन 12:00 बजे पालिताना पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09024 पालिताना - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 01 मार्च, 2026 (रविवार) को 20:00 बजे पालिताना से प्रस्थान कर अगले दिन 12:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, बोटाद, धोला, सोनगढ़ एवं सिहोर स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 03418/03417 उधना - मालदा टाउन साप्ताहिक स्पेशल (08 फेरे)

ट्रेन संख्या 03418 उधना - मालदा टाउन स्पेशल प्रत्येक सोमवार को 12:30 बजे उधना से प्रस्थान कर बुधवार को 05:55 बजे मालदा टाउन पहुँचेगी। यह ट्रेन 02 मार्च से 23 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 03417 मालदा टाउन - उधना स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 12:15 बजे मालदा टाउन से प्रस्थान कर सोमवार को 02:15 बजे उधना पहुँचेगी। यह ट्रेन 28 फरवरी, 2026 से 21 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में चलथान, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, डोंडाईचा, अमलनेर, भुसावल, इटारसी, पिपरिया, मदन महल, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, तिलैया, नवादा, शेखपुरा, किऊल, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज, बरहरवा एवं न्यू फरक्का स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

5. ट्रेन संख्या 09425/09426 साबरमती - हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09425 साबरमती - हरिद्वार स्पेशल प्रत्येक सोमवार को 18:45 बजे साबरमती से प्रस्थान कर अगले दिन 20:30 बजे हरिद्वार पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फरवरी, 2026 से 23 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09426 हरिद्वार - साबरमती स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को हरिद्वार से 21:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 22:30 बजे साबरमती पहुँचेगी। यह ट्रेन 24 फरवरी, 2026 से 24 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, जवाई बांध, फालना, रानी, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर एवं रुड़की स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

6. ट्रेन संख्या 09309/09310 इंदौर - हजरत निजामुद्दीन द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (20 फेरे)

ट्रेन संख्या 09309 इंदौर - हजरत निजामुद्दीन स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार को 17:00 बजे इंदौर से प्रस्थान कर अगले दिन 05:00 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुँचेगी। यह ट्रेन 22 फरवरी, 2026 से 27 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09310 हजरत निजामुद्दीन - इंदौर स्पेशल प्रत्येक शनिवार एवं सोमवार को हजरत निजामुद्दीन से 08:20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 21:00 बजे इंदौर पहुँचेगी।

रेलवे द्वारा होली के लिए 24 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए, रेलवे एलटीटी मुंबई-कानपुर और पुणे/हडपासर-झांसी के बीच होली के लिए 24 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाएगा। मध्य रेल ने पहले ही 216 होली विशेष ट्रेनों (186 होली विशेष और 30 अतिरिक्त होली विशेष) की घोषणा की थी और इन 24 अतिरिक्त होली विशेष ट्रेनों के चलने के साथ, अब तक घोषित होली विशेष ट्रेनों की कुल संख्या 240 हो गई है।

विवरण इस प्रकार है:

एलटीटी-कानपुर-एलटीटी साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष (8 सेवाएं)

04152 साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष प्रत्येक शनिवार को दिनांक 07.03.2026 से 28.03.2026 तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस से शाम 17:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर दोपहर 15:45 बजे पहुंचेगी। (4 सेवाएं)

04151 साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष प्रत्येक शुक्रवार को दिनांक 06.03.2026 से 27.03.2026 तक कानपुर सेंट्रल स्टेशन से 13:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर दोपहर 14:55 बजे पहुंचेगी। (4 सेवाएं)

ठहराव: भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, धभौरा, प्रयागराज, भरवारी, सिराथू और फ़तेहपुर

संरचना: 1 एसी 2-टियर, 4 एसी 3-टियर, 9 शयनयान श्रेणी, 8 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन।

पुणे-झांसी-पुणे साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष (8 सेवाएं)

01921 साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष प्रत्येक गुरुवार को दिनांक 05.03.2026 से 26.03.2026 तक पुणे से 15.15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10.00 बजे वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। (4 सेवाएं)

01922 साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष प्रत्येक बुधवार को दिनांक 04.03.2026 से 25.03.2026 तक वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी से 12.50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.35 बजे पुणे पहुंचेगी। (4 सेवा)

ठहराव: दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, विदिशा, बीना और ललितपुर

संरचना: 1 एसी 2-टियर, 3 एसी 3-टियर, 7 शयनयान, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गाड्र्स ब्रेक वैन।

हडपसर-झांसी-हडपसर साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष(8 सेवाएं)

01923 साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष प्रत्येक रविवार को दिनांक 08.03.2026 से 29.03.2026 तक हडपसर से शाम 19:10 बजे प्रस्थान करेगी ।

क्वालकॉम, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में करेंगी 'क्वालकॉम ऑटोमोटिव मॉड्यूल' का विनिर्माण

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अमेरिकी चिप कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की शुक्रवार को जानकारी दी। इसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम में 'क्वालकॉम ऑटोमोटिव मॉड्यूल' का विनिर्माण करेगी। कंपनियों की ओर से शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान के अनुसार, इस सहयोग के साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के वैश्विक मॉड्यूल विनिर्माण साझेदार नेटवर्क में शामिल हो गई है जिसका उद्देश्य 'मॉड्यूलर ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म' की बढ़ती वैश्विक मांग को समर्थन देना है। बयान में कहा गया, ' 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज अपने क्वालकॉम ऑटोमोटिव मॉड्यूल उत्पादों का विनिर्माण भारत में 'जागीरोड' (असम) में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी सेमीकंडक्टर 'असेम्बली' एवं परीक्षण इकाई में करेगी।'

क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एवं एम्बेडेड आईओटी और रोबोटिक्स समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं महाप्रबंधक नकुल दुग्गल ने कहा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ यह साझेदारी कंपनी की स्वचालन विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा, ''उद्योग के एकीकृत, मॉड्यूल-आधारित ढांचे की ओर तेजी से बढ़ने से प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता का विस्तार आवश्यक हो जाता है।''

क्वालकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सावी सोइन ने कहा, 'टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से भारत में विनिर्माण से भारतीय और वैश्विक स्तर पर ओईएम (मूल उपकरण विनिर्माण) को अधिक बल मिलेगा। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को समर्थन देने की हमारी क्षमता बढ़ेगी।' टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) रंधीर ठाकुर ने कहा कि यह सहयोग टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के वैश्विक स्तर पर उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण के केंद्र के रूप में उभरने के उद्देश्य को समर्थन देता है। उन्होंने कहा, 'हम अपने 'इंटीग्रेटेड सिस्टम्स पैकेजिंग' (आईएसपी) समाधानों का इस्तेमाल करते हुए क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज की वैश्विक उत्पाद नेतृत्व क्षमता को समर्थन देने के लिए उच्च गुणवत्ता एवं उच्च प्रदर्शन वाले उत्पाद उपलब्ध कराएंगे।' बयान के अनुसार, इस सहयोग का उद्देश्य 'डिजिटल कॉकपिट', 'इंफोटेनमेंट', 'कनेक्टिविटी' और 'इंटेलिजेंट व्हीकल सिस्टम' के लिए स्वचालन प्रौद्योगिकियों के स्थानीय उत्पादन को सक्षम बनाना है, जिससे भारतीय एवं वैश्विक मोटर वाहन विनिर्माताओं की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और भौगोलिक विविधीकरण को बढ़ाया जा सके।

टाटा समूह एआई चिप के विकास की दिशा में सक्रिय : चंद्रशेखरन

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बृहस्पतिवार को कहा कि समूह कृत्रिम मेधा (एआई) के समूचे प्रौद्योगिकी ढांचे के विकास पर काम कर रहा है और उद्योग-विशिष्ट एआई चिप विकसित करने की दिशा में भी पहल शुरू कर दी गई है। चंद्रशेखरन ने यहां आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के दौरान पीटीआई-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों पर एआई के व्यापक प्रभाव को देखते हुए टाटा समूह औद्योगिक समाधानों से लेकर डेटा सेंटर और क्षेत्र-विशिष्ट एआई समाधानों तक कई स्तरों पर अपनी क्षमता विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा, 'हम समय के साथ उद्योग के हिसाब से अलग-अलग एआई-आधारित चिप विकसित करना चाहते हैं। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है, हालांकि इसकी समय-सीमा बताना अभी संभव नहीं है।'

समूह द्वारा विकसित किए जा रहे शुरुआती सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल वाहन क्षेत्र में किए जाने की संभावना है। टाटा समूह ने एआई अवसंरचना विकसित करने के लिए अमेरिकी कंपनी ओपनएआई के साथ साझेदारी की है। इसके तहत शुरुआत में 100 मेगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर एक गीगावाट तक किया जा सकता है। समूह की आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) अमेरिकी चिप विनिर्माता एएमडी के साथ मिलकर वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत में टिकाऊ उच्च-घनत्व वाली एआई क्षमता विकसित करने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। चंद्रशेखरन ने कहा, ''टीसीएस और टाटा कम्युनिकेशंस औद्योगिक समाधान के लिए एक एआई ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित कर रही हैं, जिसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए 'एजेंटिक एआई' आधारित समाधान तैयार किए जा सकेंगे।''

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में समूह की इकाई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में ताइवानी कंपनी पीएसएमसी के साथ मिलकर करीब 91, 000 करोड़ रुपये के निवेश से एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है। इस संयंत्र में शुरुआती चरण में 28 नैनोमीटर (एनएम) तकनीक पर आधारित चिप बनाए जाएंगे जिनका उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट आधारित उपकरणों, वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्किंग उपकरणों में होता है। इसके अतिरिक्त, असम में 27, 000 करोड़ रुपये के निवेश से एक चिप पैकेजिंग इकाई भी स्थापित की जा रही है, जिससे क्षेत्र में 27, 000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि धोलेरा और असम में स्थापित किए जा रहे संयंत्रों को विभिन्न हितधारकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। टाटा समूह के चेयरमैन ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं लेकिन इसके लिए समूह को साझेदारों की भी जरूरत पड़ेगी। इस दिशा में कंपनी एएसएमएल, तोक्यो इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड मैटेरियल्स, क्वालकॉम और इंटेल जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग कर रही है।

टी20 वर्ल्ड कप : भारत के पूर्व क्रिकेटरों ने टॉप 4 की भविष्यवाणी की, पाकिस्तान को रखा बाहर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत के पूर्व क्रिकेटरों ने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनलिस्ट के बारे में भविष्यवाणी की है। सुपर 8 शनिवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच के साथ शुरू होगा। आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में रखा गया है। सभी टीमें अपने ग्रुप की दूसरी टीमों के खिलाफ तीन मैच खेलेंगी जिसमें हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

मौजूदा चैंपियन भारत 2024 की रनर-अप दक्षिण अफ्रीका, दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे ग्रुर्प में हैं। जबकि 2009 की चैंपियन पाकिस्तान, 2014 की चैंपियन श्रीलंका, दो बार की विजेता इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ग्रुप" में हैं। शुक्रवार को स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी एक वीडियो में भारत के महान टेस्ट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने टॉप चार के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को चुना। मोहम्मद कैफ ने अगले स्टेज के लिए भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को चुना।

टी20 आई में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर युजवेंद्र चहल ने टॉप चार में पहुंचने के लिए भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को चुना जबकि पूर्व तेज गेंदबाज वरुण ऑरोन ने सबसे हिम्मत वाला फैसला लेते हुए भारत, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और पाकिस्तान को चुना और खास तौर पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों को बाहर रखा।

पूर्व कोच संजय बांगर ने पाकिस्तान, भारत, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को चुना। हालांकि पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और श्रीलंका को अपने सेमी-फाइनलिस्ट के तौर पर चुना। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले की गई प्री-सीडिंग की वजह से, ग्रुप स्टेज की सभी टेबल टॉपर टीमें एक ही ग्रुप ए में आ गई हैं। जबकि दूसरे नंबर की टीमें ग्रुप बी में हैं।

इस बीच भारत सुपर 8 में अपना कैंपेन रविवार को शुरू करेगा जब उसका मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से होगा। वे अपना अगला मैच गुरुवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन सुपर8 में अपना आखिरी मैच 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप

श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंचा भारत पाकिस्तान से हो सकता है खिताबी मुकाबला

बैंकॉक। कप्तान राधा यादव ने शानदार हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए भारत ए की टीम को शुक्रवार को यहां श्रीलंका ए पर पांच विकेट से जीत दिलाकर वुमैन्स राइजिंग स्टार्स टी20 एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन यह उस पर भारी पड़ गया। राधा की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने उसके बल्लेबाजी लाइन-अप को तहस-नहस कर उन्हें 118 रन पर आउट कर दिया। बाएं हाथ की स्पिनर राधा ने 19 रन देकर चार विकेट लिए। राधा को एक और बाएं हाथ की स्पिनर तनुजा कंवर (20 रन देकर दो विकेट) और लेग स्पिनर प्रेमा रावत (नौ रन देकर दो विकेट) का अच्छा साथ मिला।

श्रीलंका के लिए सलामी बल्लेबाज संजना काविंदी (31 रन) शीर्ष स्कोरर रहीं। 10वें ओवर में श्रीलंका का स्कोर दो विकेट पर 71 रन था। लेकिन इसके बाद वे भारतीय स्पिनरों का सामना नहीं कर सकीं और बचे हुए आठ विकेट नौ ओवर में 47 रन के अंदर गंवा दिए। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी भागीदारी काविंदी और साथी सलामी बल्लेबाज हंसिमा करुणारत्ने (14) के बीच 36 रन की साझेदारी रही।

लक्ष्य का पीछा करते समय भारत ने एक समय 21 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। टीम के लिए वृंदा दिनेश 42 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। लेकिन राधा ने बल्लेबाजी में योगदान करते हुए 18 गेंदों पर सात चौकों की मदद से नाबाद 31 रन बनाए जिससे भारत ने 13.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। फाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

टी20 विश्व कप : अभिषेक शर्मा के लिए साउथ अफ्रीका का 'स्पेशल प्लान'

कप्तान मार्कराम रचेंगे स्पिन का चक्रव्यूह

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। मौजूदा टी20 विश्व कप में अभिषेक शर्मा उतने ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं, जिनमें से दो बार स्पिनरों ने उन्हें आउट किया। पिछले दो मैचों में पाकिस्तान के सलमान आगा और नीदरलैंड के आर्यन दत्त ने सलामी बल्लेबाज को आउट किया, जिससे भारत की वह कमजोरी उजागर हुई है जिसे 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर एट्स के मुकाबले से पहले दूर करना जरूरी है।

इस बीच, प्रोटियाज़ ने अभिषेक से निपटने की योजना बनाना शुरू कर दिया है। मैच से दो दिन पहले अभ्यास सत्र के दौरान, कप्तान एडन मार्कराम को बाएं हाथ के बल्लेबाज को राउंड द विकेट गेंदबाजी करते देखा गया। वह आर्यन दत्त की उस गेंद को दोहराने की कोशिश कर रहे थे, जिसने पिछले मैच में अभिषेक को आउट किया था। केशव महाराज ने भी नेट पर जमकर अभ्यास किया और इससे संकेत मिलता है कि वे पावरप्ले में स्पिनरों पर काफी भरोसा करेंगे।

लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट होने के बावजूद, अभिषेक की जगह संजू सैमसन को टीम में शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पंजाब के इस बल्लेबाज से जल्द ही फॉर्म में लौटने और अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में आने की उम्मीद है, जो पिछले साल स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी और जिसकी बदौलत वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर एक बल्लेबाज बने थे। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भारत की टीम में बदलाव की संभावना है। पिछले मैच में बेंच पर बैठे अक्षर पटेल वाशिंगटन सुंदर की जगह वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।इस बीच, यह बड़ा मुकाबला सुपर एट्स के ग्रुप ए का भविष्य तय कर सकता है। विजेता टीम के शीर्ष स्थान पर रहने की उम्मीद है, हालांकि टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब कुछ भी निश्चित नहीं है। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज, जो इस टूर्नामेंट में दो और अपराजित टीमें हैं, भी उलटफेर कर सकती हैं।

एआई का फायदा सबको मिलेगा, सुंदर पिचाई बोले- भारत और अमेरिका साझेदारी निभाएगी अहम भूमिका

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका-भारत साझेदारी की कृत्रिम मेधा (एआई) के लाभ सभी लोगों तक और हर स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका है। उन्होंने यहां 'एआई इम्पैक्ट समिट' में भारत और अमेरिका द्वारा 'पैक्स सिलिका' घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर से पहले कहा कि गूगल को दोनों देशों के बीच ''रूपक और वास्तविक'' तरीके से संपर्क सेतु के रूप में सेवा देने पर गर्व है।

पिचाई ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग एआई के लाभों को व्यापक स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पिचाई ने कहा, ' कल उद्घाटन सत्र में मैंने एआई के बेहतरीन दौर पर अपने विचार साझा किए थे। मैंने कहा था कि हम तीव्र प्रगति और नई खोजों के एक युग की दहलीज पर हैं लेकिन सर्वोत्तम परिणामों की गारंटी नहीं है। ' उन्होंने कहा, '' हमें मिलकर काम करना होगा ताकि एआई के लाभ सभी लोगों तक और हर स्थान पर उपलब्ध हों। अमेरिका-भारत साझेदारी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।''

पिचाई ने कहा कि कंपनी को अमेरिका और भारत के बीच '' रूपक व वास्तविक, दोनों ही तरीकों से ' एक संपर्क सेतु के रूप में काम करने पर गर्व है। उन्होंने विस्तार से बताया कि दोनों देशों में गूगल के दल उसकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलों पर निर्बाध रूप से साथ काम कर रहे हैं। भारत से शुरू हुए नवाचार, जैसे 'गूगल पे'.. दुनिया भर के लोगों के लिए उत्पादों को बेहतर बना रहे हैं। भारत को लेकर उत्साह जताते हुए पिचाई ने कहा, '' मेरा मानना है कि एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति असाधारण रहने वाली है और हम उत्पादों के विस्तार एवं बुनियादी ढांचे सहित पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसका समर्थन कर रहे हैं।

अमेरिका-ईरान तनाव से उछला कच्चा तेल, 6 महीने के हाई पर पहुंची कीमतें

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ छह महीने के उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे तेल बाजार में तेजी देखने को मिल रही है।

20 फरवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) लगभग 67 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है। पिछले कारोबारी सत्र में ब्रेंट 1.9इ की बढ़त के साथ 71.66 डॉलर पर बंद हुआ था और डब्ल्यूटीआई भी 1.9इ चढ़कर 66.43 डॉलर पर पहुंच गया था। पिछले दो सत्रों में कुल मिलाकर 6-7इ की तेजी दर्ज की गई है, जो जनवरी के अंत के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई न्यूक्लियर डील के लिए 10 से 15 दिन की समय-सीमा दी है और चेतावनी दी है कि असफलता की स्थिति में 'गंभीर परिणाम' हो सकते हैं। इस बयान के बाद बाजार में सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है।

मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैनाती 2003 के इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ी बताई जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि ईरान भी अपनी रणनीतिक जगहों को मजबूत कर रहा है। इससे तेल सप्लाई बाधित होने का खतरा बढ़ गया है।

विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट पर निवेशकों की नजर है, क्योंकि दुनिया के लगभग एक-तिहाई तेल का परिवहन इसी मार्ग से होता है। यदि यहां किसी प्रकार का व्यवधान आता है, तो कीमतों में और तेज उछाल संभव है।

अमेरिका में पिछले सप्ताह कच्चे तेल का भंडार लगभग 9 मिलियन बैरल घटा है, जो सितंबर के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है।

रिफाइंड प्रोडक्ट्स के स्टॉक में भी कमी आई है, जो मजबूत मांग का संकेत देता है।

इसके अलावा, ब्रेंट क्रूड के 100 डॉलर स्ट्राइक प्राइस तक के कॉल ऑप्शंस में बढ़ती खरीदारी यह दिखाती है कि निवेशक संभावित बड़े उछाल के खिलाफ हेजिंग कर रहे हैं। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए महंगा कच्चा तेल चिंता का विषय है। यदि कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं तो पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं, जिससे महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ सकता है।

अगर अमेरिका-ईरान वार्ता सफल रहती है तो कीमतों में नरमी आ सकती है लेकिन तनाव बढ़ने या सैन्य कार्रवाई की स्थिति में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

पीयूष गोयल का ऐलान : अप्रैल में लागू होगा भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता

ब्रिटेन-ओमान से भी एफटीए फाइनल

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता इस साल अप्रैल में लागू होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भी इसी महीने लागू हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के साथ यह समझौता सितंबर में लागू होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अंतरिम व्यापार समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों की तीन दिवसीय बैठक 23 फरवरी को अमेरिका में शुरू होगी। इस महीने की शुरुआत में, भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी कर घोषणा की थी कि अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तैयार कर लिया गया है। संयुक्त बयान में समझौते की रूपरेखा दी गई है। अब, समझौते की रूपरेखा को एक कानूनी समझौते में बदलना होगा, जिस पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे। उम्मीद है कि इस पर मार्च में हस्ताक्षर हो जाएंगे। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि यूरोपीय संघ के सभी 27 देश इस एफटीए को अंतिम रूप दिए जाने और जल्द से जल्द आगे बढ़ाए जाने के लिए उत्सुक हैं। यह 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है।भारतीय दल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव दर्पण जैन करेंगे, जो मुख्य वार्ताकार हैं। अंतरिम व्यापार समझौते के तहत, दोनों पक्ष आपस में व्यापार की जाने वाली कई वस्तुओं पर एक-दूसरे को शुल्क में छूट देंगे। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। उसने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क को पहले ही समाप्त कर दिया है।

बाफ्टा 2026: प्रियंका चोपड़ा और दीपिका के बाद आलिया भट्ट बनीं प्रेजेंटर, सिलियन मर्फी के साथ साझा करेंगी मंच

मुंबई। भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार आलिया भट्ट वैश्विक मंच पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही हैं। आलिया 22 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित होने वाले 79वें बाफ्टा अवॉर्ड्स में एक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही वह प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने पूर्व में इस प्रतिष्ठित ब्रिटिश मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

ऑर्गनाइज़र्स ने कन्फर्म किया है कि आलिया एलिसिया विकेंडर, सिलियन मर्फी, एमिली वॉटसन और एथन हॉक जैसे गेस्ट प्रेजेंटर्स की शानदार लिस्ट में शामिल होंगी। ये अवाड्र्स, जिन्हें ऑफिशियली "बाफ्टा फिल्म अवाड्र्स के नाम से जाना जाता है। आलिया का आना इंडियन स्टार्स प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के नक्शेकदम पर है, जिन्होंने पिछले सालों में सेरेमनी में प्रेजेंटेशन दिया है।

मंगलवार को, बाफ्टा ने अवार्ड प्रेजेंटर्स की लिस्ट जारी की, जिसमें आलिया भट्ट अकेली इंडियन सेलिब्रिटी थीं जो मौजूद थीं। उनके अलावा, इस साल बाफ्टा अवाड्र्स में हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स भी अवार्ड प्रेजेंटर के तौर पर मौजूद रहेंगे। इनमें शामिल हैं: ब्रायन क्रैंस्टन, एरॉन पियरे, सिलियन मर्फी, एमी लू वुड, एलिसिया विकेंडर, नोआ जूप, ओलिविया कुक, पैट्रिक डेम्पसी, रेगे-जीन पेज, एथन हॉक, गिलियन एंडरसन, ग्लेन क्लोज़, हन्नाह वाडिंगहैम, केट हडसन, कैथरीन हैन, केरी वाशिंगटन, लिटिल सिम्ज़, मैगी गिलेनहाल, डेविड जॉनसन, डेलरॉय लिंडो, एमिली वॉटसन, स्टॉर्मज़ी, वारविक डेविस, एरिन डोहर्टी, स्टेलन स्कार्सगार्ड, मिया मैककेना-ब्रूस, माइकल बी जॉर्डन, माइल्स कैटन, मिली एल्कॉक, मिन्नी ड्राइवर, मोनिका बेलुची, सैडी सिंक और रिज़ अहमद। आलिया के अलावा, फिल्ममेकर लक्ष्मीप्रिया देवी भी इस सेरेमनी में शामिल होंगी क्योंकि उनकी मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग को बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है।

बिग बॉस 20 : क्या सलमान खान के शो में होगी रिधिमा गुप्ता की एंट्री? एक्ट्रेस की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

रियलिटी शो के बादशाह 'बिग बॉस' के अगले सीजन यानी बिग बॉस 20 को लेकर चर्चाएं अभी से तेज हो गई हैं। सलमान खान के इस बहुप्रतीक्षित शो की प्री-प्रोडक्शन प्रक्रिया जोरों पर है और इसी बीच टीवी अभिनेत्री रिधिमा गुप्ता की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस के बीच अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है।

माना जा रहा है कि कास्टिंग प्रोसेस चल रहा है, फैंस उन टेलीविज़न पर्सनैलिटीज़ के सोशल मीडिया इंटरैक्शन को करीब से फ़ॉलो कर रहे हैं जो इस साल जल्द ही बिग बॉस के घर के अंदर आ सकते हैं। जैसा कि पिछले सीज़न में होता आया है, ज़रा सा इशारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस का तूफ़ान खड़ा करने के लिए काफ़ी है।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

इंजीनियरिंग विभाग : ई–टेंडरिंग सूचना

संख्या : W/623/5/1/NIT, दिनांक : 16.02.2026, मंडल रेल प्रबंधक/ मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ''खुली निविदा'' ई–निविदा के माध्यम से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है।

क्र. संख्या : 1, **ई–टेंडरिंग संख्या :** RTM-2025-26-186, **कार्य का नाम :** Ratlam- Improvement to water supply and sanitary system in old colony road no 4-7 and new colony road no 1-4, **अनुमानित लागत :** ₹ 1,80,80,019.56, **बयाना राशि :** ₹ 2,40,400.00, **निविदा खुलने की तिथि :** 12.03.2026. **क्र. संख्या :** 2, **ई–टेंडरिंग संख्या :** RTM-2025-26-187, **कार्य का नाम :** Ratlam Division - Providing 08 Nos Bore Well to increase the own water source in Railway Premises. (Composite Civil + Electrical, **अनुमानित लागत :** ₹ 31,21,103.24, **बयाना राशि :** ₹ 62,400.00, **निविदा खुलने की तिथि :** 12.03.2026.विस्तृत निविदा सूचना अर्हता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।

ADM/5/1/464

Follow us on: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मंडल

इलेक्ट्रिकल कार्य

ई-निविदा - सूचना संख्या. व.मं.बि. इंजी/अह./44 (25-26) **दिनांक: 19.02.2026**
निविदा संख्या EL-50-1-ADI-T-54-2025-26

कार्य का नाम: पालनपुर - समाख्याली खंड पर अडेसर - लखपतनगर स्टेशनों के बीच रेलवे किलोमीटर 186/8-9 पर मौजूदा आरओबी संख्या (142 ए) के निर्माण, वटवा यार्ड में सीपीओएच, जेडएमसी और रनिंग रूम से कनेक्ट करने के लिए RUB, SDRH-GIMB के ऑपरेशन थिएटर में एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था, गांधीधाम में एसी लोकोमोटिव के लघु अनुसूची निरीक्षण के लिए ट्रिप निरीक्षण/अग्रिम निरीक्षण केंद्र की सुविधाओं का उन्नयन, चांदलोडिया और असारवा में अमृत स्टेशन के विकास के संबंध में दिव्यांगजनों और यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार और लाइन संख्या 08 और 09 के बीच स्थित प्लेटफार्म पर पूर्ण लंबाई वाले कवर शेड का विकास संबंधित इलेक्ट्रिकल कार्य।

अनुमानित लागत: ₹ 3,50,87,324/-

बयाना राशि: ₹ 3,25,400/-

निविदा प्रपत्र जमा करने की आखिरी तारीख एवं समय: 18.03.2026 को 15:00 बजे तक

निविदा प्रपत्र खुलने की तारीख एवं समय: 18.03.2026 को 15:30 बजे.

ऑफिस का पता: वरि. मण्डल बिजली इंजीनियर. डी. आर.एम. ऑफिस, चामुंडा पुल के पास, जी.सी.एस.अस्पताल के सामने, नरोड़ा रोड, अमदुपुरा, अहमदाबाद-382345

वेब साइट का पता: www.ireps.gov.in ADI 280

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

एआई की सहायता लें, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर न रहें – डॉ. अशोक कुमार वार्ष्णेय

एआई का सेवक नहीं, स्वामी बनकर प्रयोग करें – डॉ. जी. एस. तोमर

गोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में 'डिजिटल हेल्थ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एवं स्मार्ट फ़ार्मा' विषय पर द्विदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत सहित कई देशों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने सहभागिता की।

सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के तकनीकी सलाहकार डॉ. जी. एन. सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. के. आर. सी. रेड्डी तथा मलेशिया से डॉ. कंचन कोहली उपस्थित रहीं। अध्यक्षता महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने की।

एक वैज्ञानिक सत्र में बतौर मुख्य अतिथि वक्ता आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव, आयुष मंत्रालय (भारत सरकार) के पूर्व सलाहकार एवं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सदस्य डॉ. अशोक कुमार वार्ष्णेय ने 'वैश्विक स्वास्थ्य के लिए विज्ञान एवं पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली

के बीच संतुलन' विषय पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता को देखते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में सशक्त स्थान दिलाने की आवश्यकता है। इसके लिए चिकित्सकों और शोधार्थियों को विज्ञान तथा पारम्परिक चिकित्सा के बीच संतुलन साधना होगा।

डॉ. वार्ष्णेय ने बताया कि डिजिटलीकरण और एआई इस लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर एक चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जबकि आयुष चिकित्सकों को मिलाकर देश में औसतन प्रति 811 जनसंख्या पर एक चिकित्सक उपलब्ध है। हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच यह अंतर अभी भी बड़ा है, जिसे डिजिटलीकरण और एआई के माध्यम से कम किया जा सकता है। कोविड काल में टेलीमेडिसिन के सफल प्रयोग ने इसकी उपयोगिता सिद्ध कर दी है।

वॉरगेमिंग और सिमुलेशन से बढ़ाई जाएगी सैन्य निर्णय लेने की क्षमता, भारतीय सेना ने बनाया ये प्लान

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में 'इनहेंसिंग मिलिट्री डिसीजन मेकिंग थ्रू वॉरगेमिंग एंड सिमुलेशन - ब्रिजिंग नॉलेज एंड इंडस्ट्री गैप्स' विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमिनार वॉरगेमिंग डेवलपमेंट सेंटर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देशभर के वॉरगेमिंग इकोसिस्टम से जुड़े वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, शिक्षाविद, रणनीतिक विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकी उद्योग के विशेषज्ञ शामिल हुए।

सेमिनार का उद्देश्य समकालीन और भविष्य के मल्टी-डोमेन युद्धक्षेत्र में ऑपरेशनल प्लानिंग, नेतृत्व विकास और सिद्धांत नवाचार के लिए वॉरगेमिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्थापित करना रहा। सेमिनार का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने किया।

निर्णय क्षमता को धार देने का सशक्त माध्यम है वॉरगेमिंग : लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा

लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वॉरगेमिंग केवल एक प्रक्रियात्मक अभ्यास नहीं बल्कि रणनीतिक निर्णय क्षमता को धार देने, धारणाओं को परखने और अनुकूलनशील सोच विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने संस्थागत योजना प्रक्रियाओं में सिमुलेशन आधारित विश्लेषण को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि ऑपरेशनल तैयारी, निर्णय श्रेष्ठता और गतिशील चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा के संबोधन में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बढ़ते जोर और उन्नत क्षमताओं के स्वदेशी विकास, डिजाइन और तैनाती के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता भी परिलक्षित हुई। सेमिनार में सैन्य, शैक्षणिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सैन्य परिप्रेक्ष्य में मल्टी-डोमेन सिमुलेशन के उपयोग, वॉरगेमिंग को एक मुख्य पेशेवर दक्षता के रूप में संस्थागत रूप देने और तेज, अस्पष्ट तथा तकनीकी रूप से जटिल वातावरण में कमांडरों को तैयार करने पर जोर दिया गया।

तीन स्वदेशी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हुए जारी

इसके साथ आयोजित प्रदर्शनी में उन्नत सिमुलेशन प्लेटफॉर्म और अभिनव तकनीकी समाधानों का प्रदर्शन किया गया। सेमिनार के दौरान WARDEC द्वारा विकसित तीन स्वदेशी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी जारी किए गए। इनमें ऑटो इवैल्यूएशन मैप मार्किंग टूल, कॉम्बैट डिसीजन रिजोल्यूशन वर्जन 9 और ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस प्रिपरेशन ऑफ द बैटलफील्ड शामिल हैं। ये एप्लीकेशन कमांडरों के लिए संरचित निर्णय-सहायता ढांचा प्रदान करते हैं और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भारतीय सेना की प्रगति को दर्शाते हैं।

दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़! नमाज-आरती एक ही समय होने से दो पक्षों में भड़का विवाद, पथराव से इलाके में तनाव

भोपाल **(एजेंसी)**। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा क्षेत्र में शुक्रवार को आजाद चौक इलाके में पथराव की घटना सामने आई, जिसके बाद कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि विवाद आरती के दौरान एक युवक से मारपीट और तोड़फोड़ के बाद बवाल हो गया। दो समुदाय आमने-सामने आ गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे स्थानीय चैनल का लाइव फुटेज बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हल्का बल प्रयोग कर हालात को नियंत्रित कर लिया है।

बताया जा रहा है कि आजाद चौक क्षेत्र में मंदिर और मस्जिद आमने-सामने स्थित हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक ही समय पर मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज़ के चल रहा था। इसी दौरान एक समुदाय विशेष के युवक ने

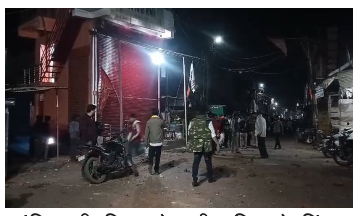

मंदिर की ग्रिल तोड़ दी। जिससे हिंदू पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना अचानक शुरू हुई जिससे आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बल मौके पर पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है और माहौल अब शांतिपूर्ण है। वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने की अपील भी प्रशासन की ओर से की गई है। मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसी घटना जिससे आपसी सौहर्द बिगड़ता है, उसमें सरकार संज्ञान लेगी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में घटना है।

नगर निगम चुनाव प्रचार का शोर बना बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए परेशानी, अभिभावकों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

रांची **(एजेंसी)**। नगर निगम चुनाव के दौरान बज रहे लाउडस्पीकरों का तेज शोर इन दिनों बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। कई इलाकों से शिकायत मिल रही है कि तय समय के बाद भी प्रचार में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान शहर के अलग-अलग इलाकों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बज रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि इससे

बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। देर रात तक शोर रहने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है। कांके रोड निवासी राजेश कुमार ने बताया कि उनका बेटा इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन कई बार रात 10 बजे के बाद भी लाउडस्पीकर बजते रहते हैं। दिनभर प्रचार वाहनों से तेज आवाज में अनाउंसमेंट किया जाता है। समझाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। बरियातू की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया कि उनकी बेटी मैट्रिक की छात्रा है। परीक्षा के समय इस तरह का शोर बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ा रहा है। डोरंडा इलाके के एक अन्य अभिभावक ने भी कहा कि दिन में स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और शाम-रात का समय ही पढ़ाई के लिए मिलता है, लेकिन प्रचार का शोर पढ़ाई में बाधा बन रहा है।

इस समय राज्य में झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में स्कूलों और आसपास के इलाकों में शांति और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाउडस्पीकर का उपयोग केवल तय समय सीमा के अंदर ही किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक है।

दामोदर यादव के खिलाफ उतरा दलित समाज!

एनएसए लगाने की उठाई मांग हो रहा संकल्प यात्रा का विरोध

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। नगर पार्षद रामवीर जाटव ने खुलकर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दामोदर यादव पर एनएसए लगाने और उनकी सभाओं पर रोक लगाने की मांग की है। रामवीर जाटव का आरोप है कि दामोदर यादव बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और समाज के युवाओं को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि दामोदर यादव कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर दलित समाज के युवाओं को मोहरा बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या विवादित बयानों पर कानूनी कार्रवाई होगी या मामला राजनीतिक बहस तक सीमित रहेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक समरसता और आपसी सम्मान भी आवश्यक हैं। सभी पक्षों से संयम और जिम्मेदारी की अपेक्षा है।

नामग्या सी. खम्पा ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में किया भारत का प्रतिनिधित्व

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। भारत ने 19 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के गाजा शांति बोर्ड की पहली बैठक में 'पर्यवेक्षक' के रूप में भाग लिया। नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास की चार्ज डी'अफेयर्स नामग्या चोडेन खम्पा ने किया। भारत ने 22 जनवरी को दावोस में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था, जहां ट्रंप ने औपचारिक रूप से बोर्ड ऑफ पीस का अनावरण किया था। यह पहल गाजा में दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देने और संभावित रूप से अन्य वैश्विक संघर्षों को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह बोर्ड ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में एक संस्था स्थापित करने और विश्व मुद्दों को हल करने का प्रयास है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, नामग्या सी खम्पा 2000 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। फरवरी 2026 तक, वह वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में चार्ज डी'अफेयर्स और उप मिशन प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, जहां वह राजदूत की अनुपस्थिति में मिशन का नेतृत्व करती हैं और भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों के प्रमुख पहलुओं का प्रबंधन करती हैं।

अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, उन्होंने केन्या में भारत की उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विकास सहयोग का विस्तार करने के लिए काम किया। 2023 में, नैरोबी में रहते हुए, उन्हें सोमालिया में भारत की राजदूत के रूप में भी मान्यता दी गई थी। अपने करियर के पूर्व में, खम्पा नेपाल के काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में उप मिशन प्रमुख थीं। उन्होंने चीन में दो बार कार्य किया है, जहां उन्होंने 2002 से 2006 और फिर 2013 से 2016 तक भारत के राजनयिक मिशन में सेवाएं दीं। 2009 से 2013 तक, वे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में तैनात रहीं। इस दौरान, वे 2011 से 2013 तक संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय मामलों की सलाहकार समिति की सदस्य चुनी गईं और उन्होंने यूएनडीपी और यूएनएफपीए के कार्यकारी बोर्डों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका और म्यांमार के साथ संबंधों से संबंधित विभागों का नेतृत्व किया। 2016 से 2018 के बीच, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया। 2018 से 2020 तक, उन्होंने विदेश मंत्रालय में विकास साझेदारी प्रभाग का नेतृत्व किया, जहाँ उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ भारत की अनुदान सहायता और विकास सहयोग का प्रबंधन किया।

कर्नाटक में जुलूस पर पथराव के बाद सांप्रदायिक तनाव, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार

बेंगलुरु **(एजेंसी)**। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान गुरुवार रात पत्थर फेंके जाने की एक घटना सामने आई, जिसके बाद एहतियातन प्रशासन ने 24 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस ने मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है और कहा है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं तथा किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम जुलूस जब कस्बे की एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था, उसी दौरान संक्षिप्त पत्थरबाजी की घटना हुई। कुछ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि मस्जिद की ओर से जुलूस पर पत्थर फेंके गए। हालांकि पुलिस ने कहा है कि फिलहाल किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारियों के मुताबिक पत्थर कहां से आए, इसका पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी और अन्य वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है।

बागलकोट के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ गोयल ने बताया कि कुल दो पत्थर फेंके गए, जो पुलिसकर्मियों की ओर गिरे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी आम नागरिक को चोट नहीं आई है। पत्थर हेलमेट पहने पुलिसकर्मियों को लगे और उन्हें केवल हल्की चोटें आईं। उन्होंने गंभीर चोट या बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरों को अफवाह बताया।

पुलिस के अनुसार दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के बीच शुरू हुआ जुलूस घटना के बाद भी करीब डेढ़ घंटे तक जारी रहा और बाद में शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। अधिकारी ने बताया कि लोग बिना किसी हंगामे के अपने-अपने घर लौट गए और कहीं भी भीड़ जमा नहीं है। फिलहाल पूरे इलाके में शांति बनी हुई है।

पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पत्थरबाजी के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो साक्ष्यों के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान भी की जा रही है। पर्याप्त सबूत मिलने पर और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है।

स्पाइसजेट पर बांग्लादेश की प्रवेश प्रतिबन्धित

भारतीय उड़ानों के लिए बंद किया अपना हवाई क्षेत्र, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

ढाका **(एजेंसी)**। बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को उसके हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया है। यह कदम बकाया भुगतान के चलते उठाया गया है। इसके असर से कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली कुछ उड़ानों को अब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इस वजह से उड़ान की अवधि बढ़ सकती है और परिचालन लागत पर भी असर पड़ सकता है।

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन संबंधित अधिकारियों के साथ नेविगेशन शुल्क और अन्य परिचालन मामलों को लेकर नियमित संपर्क में है। उन्होंने इसे उद्योग के सामान्य मामले के रूप में बताया और कहा कि समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। प्रवक्ता ने पुष्टि की कि निर्धारित उड़ान सेवाएं नियमों के अनुसार जारी हैं और यात्रियों पर फिलहाल कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ा है। बकाया राशि न चुकने के कारण बांग्लादेश ने हवाई क्षेत्र बंद किया है। इससे कुछ उड़ानों को वैकल्पिक लंबी दूरी के मार्ग से संचालित करना पड़ रहा है। हालांकि एयरलाइन ने कहा कि सभी उड़ानें निर्धारित नियमों के अनुसार चल रही हैं। बकाया राशि और उसकी प्रकृति के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।

फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि कई उड़ानें बांग्लादेशी हवाई क्षेत्र को टालकर लंबा मार्ग ले रही हैं। इसी बीच, बीएसई में स्पाइसजेट के शेयरों में लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। एयरलाइन ने हाल ही में दिसंबर 2025 तिमाही में ?269.27 करोड़ का घाटा बताया, जिसका मुख्य कारण बढ़ती परिचालन लागत और एकमुश्त खर्च बताया गया है।

स्पाइसजेट ने साफ किया है कि इस प्रतिबंध के बावजूद निर्धारित उड़ानें समय पर चल रही हैं। एयरलाइन लगातार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।

युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का सुपर धमाका अब दुनिया के सामने खुलेगा एलियंस का राज!

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि दूसरे ग्रहों के प्राणियों और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं से जुड़ी तमाम गोपनीय सरकारी फाइलें अब जनता के सामने रखी जाएंगी। ट्रंप के इस फैसले से अंतरिक्ष प्रेमियों और वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

ट्रंप ने युद्ध सचिव और खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिया है कि दशकों से छिपाई गई टॉप सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा, एलियंस और यूएफओ को लेकर लोगों में भारी उत्सुकता है। वे सालों से सच का इंतजार कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि सच्चाई उनके सामने हो।

फाइलें खोलने के आदेश के साथ

ही ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी बड़ा हमला बोला। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ओबामा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसी गोपनीय जानकारियां साझा की थीं जिन्हें छिपाकर रखा जाना चाहिए था। ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में नया विवाद पैदा कर दिया है।

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास यूएफओ को लेकर कई ऐसी फाइलें हैं जो सालों से बंद पड़ी हैं। ट्रंप के इस कदम के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका के उस रहस्यमयी ठिकाने की सच्चाई सामने आएगी जहां एलियंस के होने के दावे किए जाते हैं। पेंटागन के पास मौजूद उन वीडियो और सबूतों का खुलासा होगा जो अंतरिक्षीय जीवन की ओर इशारा करते हैं। क्या अमेरिका के पास दूसरे ग्रहों की कोई तकनीक है? इसका राज भी खुल सकता है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)